छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश एवं नई दिल्ली से एक साथ प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र

रायपुर

शुक्रवार 16 अक्टूबर 2026

वर्ष-07, अंक-288

पृष्ठ-08, मूल्य- दो रुपए

हमारा उद्देश्य सेवा समर्पण जनकल्याण

एक सत बुलेटिन

E-mail: eksatbulletin@gmail.com Website: www.eksatbulletin.in

न्यूज इन शॉर्ट

बेटियां शिक्षित तो समाज सशक्त- यूपी योगी ने बताया मां स्कंदमाता की आराधना का महत्व



नई दिल्ली। सीएम योगी ने कहा कि जब नारीशक्ति स्वस्थ-शिक्षित और समर्थ होती है, तभी राष्ट्र का वर्तमान सुरक्षित और भविष्य उज्ज्वल होता है। उन्होंने मां स्कंदमाता को वात्सल्य, ममता और पोषण की अधिष्ठात्री देवी बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जगतजननी मां भगवती के स्कंदमाता स्वरूप को वात्सल्य, ममता और पोषण की अधिष्ठात्री देवी बताया। उन्होंने कहा कि मां स्कंदमाता की आराधना हमें यह पावन संदेश देती है कि जब नारीशक्ति स्वस्थ, शिक्षित और समर्थ होती है, तभी राष्ट्र का वर्तमान सुरक्षित और भविष्य उज्ज्वल होता है।केवल अपने राजनीतिक कुनबे को पोषित करने में व्यस्त थीं।

सूरत में जानवरों की दवाई बच्चों के लिए बेच रहा था मेडिकल स्टोर मालिक, री-पैकिंग करके वसूल रहा था डबल दाम



नई दिल्ली। सूरत में एक मेडिकल स्टोर संचालक को बच्चों की नकली दवा बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी जानवरों के टॉनिक को छोटी बोतलों में भरकर उस पर Li1।52 ड्रॉप्स का नकली लेबल लगाकर बेच रहा था।गुजरात के सूरत में बच्चों की दवा के नाम पर फर्जीवाड़े का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां एक मेडिकल स्टोर का मालिक जानवरों के लिए बने टॉनिक को छोटी बोतलों में भरकर और उन पर बच्चों की दवा के नकली लेबल लगाकर बेच रहा था। जानकारी मिलने पर पुलिस और फूड एंड ड्रग्स कंट्रोल मारकर आरोपी को गिरफ्तार किया।डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजदीपसिंह नकुम ने बताया कि की टीम ने मंगलवार को शहर के गोपीपुरा इलाके में 'शांतिनाथ मेडिकल स्टोर' पर छापा मारा। इस दौरान मौके से मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार किया।

भारतीय सेना को मिले स्वदेशी 450 घातक कामिकाजे ड्रोन, सिंगल बैच में सबसे बड़ी सप्लाई



नई दिल्ली। सोलर डिफेंस ने भारतीय सेना को एक ही बैच में 450 लोइटरिंग म्यूनिशन की आपूर्ति कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह स्वदेशी आपूर्ति भारत की रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए स्वदेशी डिफेंस कंपनी सोलर डिफेंस ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने भारतीय सेना को एक ही बैच में 450 लोइटरिंग म्यूनिशन की सप्लाई पूरी की है। कंपनी के मुताबिक, यो एक बार में की गई अब तक की सबसे बड़ी सप्लाई है। लोइटरिंग म्यूनिशन ऐसे हथियार होते हैं, जो लक्ष्य के आसपास कुछ समय तक उड़ान भर सकते हैं ।

पाकिस्तान में स्कूल की छत गिरने से 35 की मौत-इनमें 34 बच्चे, 1 महिला टीचर



पेशावर। पाकिस्तान के पेशावर में गुरुवार को एक प्राइवेट स्कूल की छत गिरने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 35 हो गया है। इनमें 34 छात्र और एक महिला टीचर शामिल हैं। सभी बच्चों की उम्र 13 साल या उससे कम है। हादसे के बाद निजी स्कूल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है।यह हादसा दीर कॉलोनी इलाके में हुआ। इसमें 40 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। उनके इलाज के लिए अस्पताल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में डॉक्टरों और दूसरे कर्मचारियों को तैनात किया गया है।पाकिस्तान में पिछले 6 महीने में स्कूली हादसे का यह चौथा मामला है।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में हुए शामिल

नक्सलवाद से मिले घावों पर मरहम लगाकर हर पीड़ित को सम्मानपूर्ण जीवन देना हमारा संकल्प

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि नक्सलवाद समाप्त होने के बाद अब उससे मिले घावों पर मरहम लगाना, पीड़ितों का पुनर्वास करना और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नक्सलवाद ने पाँच दशकों तक बस्तर के गरीब और आदिवासी परिवारों को गहरी पीड़ा दी है। अब हमें नक्सलवाद की हर निशानी मिटाकर बस्तर को फिर से हँसता-खेलता, खुशहाल और समृद्ध बनाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्रत्येक दिव्यांगजन और नक्सली हिंसा से प्रभावित व्यक्ति के पुनर्वास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस संकल्प को पूरा करने में भारत सरकार छत्तीसगढ़ सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है।

नक्सलवाद से मिले घावों पर मरहम लगाकर हर पीड़ित को सम्मानपूर्ण जीवन देना हमारा संकल्प

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के रूप में सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संचालित 'सेवा संकल्प अभियान' के अंतर्गत दंतेवाड़ा में आयोजित निःशुल्क दिव्यांगजन कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शिविर के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।



दंतेवाड़ा में 15 से 17 अक्टूबर तक आयोजित तीन दिवसीय शिविर में दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिलों के कुल 768 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं विभिन्न सहायक उपकरणों से लाभान्वित किया जाएगा। इनमें दंतेवाड़ा जिले के 509, बीजापुर के 197 और सुकमा के 62 दिव्यांगजन शामिल हैं। शिविर का आयोजन भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर तथा सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है।

नक्सलवाद समाप्त हुआ, अब उसकी पीड़ा और निशानियों को भी मिटाना है : श्री अमित शाह



केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर देशभर में सेवा संकल्प अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा से प्रभावित दिव्यांग आदिवासी भाई-बहनों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदान कर उनके जीवन को सुगम बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि 5 से 7 अक्टूबर 2026 के दौरान जगदलपुर में आयोजित शिविर में 3,600 से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हुए थे। इनमें अकेले बस्तर के 1,570 से अधिक लाभार्थी थे। यह संख्या बस्तर की उस पीड़ा का परिचय देती है, जिसे यहाँ के गरीब और आदिवासी परिवारों ने दशकों तक सहन किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब

मुंबई के ऑटो-टैक्सी चालकों को मराठी सीखना जरूरी

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य करने के मामले में महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। राज्य सरकार ने 1 मई 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी किया था।महाराष्ट्र में ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा सीखने की अनिवार्यता का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला माना। साथ ही कहा कि इससे जुड़े कई महत्वपूर्ण कानूनी सवालों पर विचार करने की जरूरत है।जस्टिस पी। नरसिम्हा और जज आलोक अराधे की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कहा कि इस याचिका पर महाराष्ट्र सरकार जवाब दे। क्योंकि ये एक आम जनता जनता से जुड़ा मामला है और इसे संज्ञान में लिया जाए। एक ऑटो-टैक्सी चालक ने संबंधित अधिसूचना को लेकर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

महाराष्ट्र सरकार ने 1 मई से लागू किया था नियम

महाराष्ट्र सरकार ने 1 मई 2026 से सभी ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य कर दिया। साथ ही मराठी भाषा में व्यावहार नहीं करने पर ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट कर कैंसिल करने की बात कही। इस मामले में बॉम्बे हाई



कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। हालांकि, हाई कोर्ट ने इसे यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य सरकार ने खुद मराठी सीखने की मोहलत एक साल बढ़ाई है।ऑटो-टैक्सी चालक ने इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विवेक शुक्ला और संजय पारिख ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि संबंधित अधिसूचना संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। इससे नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं और यह मोटर वाहन अधिनियम के नियमों के भी अनुरूप नहीं है।वकीलों ने कहा कि यह मामला केवल एक ऑटो-टैक्सी चालक तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे बड़ी संख्या में ऑटो-टैक्सी चालकों के अधिकार और हित जुड़े हुए हैं। इसलिए इस मामले में कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर विस्तार से विचार करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने दलीलों पर गौर करते हुए कहा कि मामले में कई महत्वपूर्ण कानूनी सवाल हैं, जिन पर हाई कोर्ट को विचार करना चाहिए।इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए महाराष्ट्र सरकार से मराठी भाषा अनिवार्य करने को लेकर जवाब तलब किया है।

53 करोड़ ग्राहकों के दम पर जियो का 30,188 करोड़ का ऐतिहासिक IPO, डिजिटल क्रांति को मिलेगी नई रफ्तार

उदय कोटक ने बताया ऐतिहासिक पड़ाव, ईशा अंबानी ने साझा की स्थापना की कहानी, आकाश अंबानी ने खोला भविष्य की योजनाओं का खाका

मुंबई। रिलायंस समूह की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स भारत के डिजिटल बाजार में अपनी मजबूत स्थिति के साथ विकास के अगले चरण की ओर बढ़ रही है। 15 अक्टूबर 2026 को आयोजित IPO मीडिया सम्मेलन में उदय कोटक, ईशा अंबानी और आकाश अंबानी ने कंपनी की उपलब्धियों, वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। उदय कोटक के अनुसार, जियो का IPO ऊपरी मूल्य दायरे पर ?30,188 करोड़ का होगा, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा।

दस साल में बदली इंटरनेट की दुनिया

उदय कोटक ने कहा कि वर्ष 2016 में जियो के आगमन ने भारत में मोबाइल कनेक्टिविटी और डेटा सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगभग 53 करोड़ ग्राहकों के साथ जियो ने डिजिटल सेवाओं के विस्तार में अहम योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि जियो का IPO निवेशकों को भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के भविष्य में भागीदारी का अवसर दे सकता है।

ईशा अंबानी ने जियो की शुरुआत से जुड़ा अनुभव साझा करते हुए बताया कि वर्ष 2009-10 के दौरान भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्याओं ने एक ऐसी कंपनी बनाने की सोच को जन्म दिया, जो देश में डिजिटल सेवाओं को व्यापक और किफायती बना सके। वर्ष 2016 में जियो की शुरुआत इसी सोच का परिणाम थी। उन्होंने कहा कि रिलायंस की कारोबारी रणनीति



दीर्घकालिक सोच, बड़े पैमाने पर विस्तार और प्रभावी क्रियान्वयन पर आधारित है।

1.46 लाख करोड़ से अधिक राजस्व, EBITDA 76,000 करोड़ पार

आकाश अंबानी ने बताया कि जियो का राजस्व पिछले तीन वर्षों में लगभग 1.09 लाख करोड़ से बढ़कर 1.46 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। कंपनी का EBITDA भी लगभग ?54,000 करोड़ से बढ़कर 76,000 करोड़ से अधिक पहुंच गया। पहली तिमाही में EBITDA मार्जिन 53.3 प्रतिशत रहा।

उन्होंने बताया कि जियो भारत के कुल डेटा ट्रैफिक का 60 प्रतिशत से अधिक वहन करता है और उसके ग्राहकों की औसत मासिक डेटा खपत 43.7 GB है। कंपनी ने अपने 5ल नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया है और दूरसंचार के साथ डिजिटल तकनीक में भी अपनी क्षमताएं मजबूत की हैं।

5ल, ब्रॉडबैंड और AI पर बड़ा दांव

आकाश अंबानी ने भविष्य की विकास योजनाओं में मोबाइल सेवाओं, होम ब्रॉडबैंड, एंटरप्राइज डिजिटल सेवाओं और तकनीकी समाधानों के विस्तार को प्रमुख बताया। जियो का लक्ष्य अपने होम ब्रॉडबैंड ग्राहक आधार को लगभग तीन करोड़ से बढ़ाकर दस करोड़ तक पहुंचाना है। कंपनी वायरलेस तकनीक के जरिए छोटे शहरों और अन्य क्षेत्रों में भी अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है।

ढ़ के क्षेत्र में कंपनी वॉइस आधारित सेवाओं पर काम कर रही है, जिनके जरिए बातचीत का सारांश और लिखित विवरण तैयार करने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। कंपनी अपनी तकनीक को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में साझेदारी के माध्यम से पहुंचाने की भी योजना बना रही है। आकाश अंबानी ने 6ल तकनीक को लेकर भी भविष्य की तैयारी का उल्लेख किया।IPO के साथ अगली पीढ़ी के नेतृत्व की नई चुनौतीउदय कोटक ने आकाश और ईशा अंबानी के नेतृत्व को रिलायंस समूह के नए दौर के कारोबारों के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण बताया। जियो की यात्रा सस्ते इंटरनेट से शुरू होकर अब 5ल, ब्रॉडबैंड, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ढ़ तक पहुंच चुकी है।30,188 करोड़ के प्रस्तावित IPO के साथ कंपनी के सामने अपने विशाल ग्राहक आधार को टिकाऊ विकास और नई तकनीकी सेवाओं में बदलने की चुनौती होगी। निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि जियो अपनी मजबूत बाजार स्थिति का उपयोग भविष्य में किस तरह नए कारोबारी अवसरों में करती है।

कहा- महिला हॉकी में 44 साल का इंतजार खत्म हुआ; इनकी सफलता, देश की सफलता

पीएम मोदी दिल्ली में एशियन गेम्स मेडलिस्ट से मिले

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एशियन गेम्स 2026 के मेडलिस्ट खिलाड़ियों से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम की तारीफ करते हुए कहा कि टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर 44 साल का इंतजार खत्म किया है। खिलाड़ियों की सफलता देश की सफलता है।

ई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में यह कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा भी शामिल रहीं।आइची-नागोया में हुए एशियाई खेलों में भारत ने कुल 85 पदक जीते।



इनमें 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज शामिल हैं। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा।

भारतीय विमेंस हॉकी टीम ने 44 साल बाद गोल्ड जीता

भारतीय विमेंस हॉकी टीम ने एशियन गेम्स के फाइनल में भारत ने चीन को 1-0 से हराया था। टीम के लिए एकमात्र गोल लालरेमसियामी ने किया। भारत ने इससे पहले 1982 में साउथ कोरिया को हराकर गोल्ड जीता था।मोदी पहले भी कई मौकों पर भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात कर चुके हैं। पिछली बार वे 9 अगस्त को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के मेडलिस्ट से मिले थे।

न्यूज इन शॉर्ट



प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से आत्माराम साहू के बिजली बिल की चिंता हुई दूर

रायपुर। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ने राजनांदगांव जिले छुरिया विकासखंड के वनांचल ग्राम मासूल निवासी श्री आत्माराम साहू के जीवन में बचत और आत्मनिर्भरता की नई रोशनी लाई है। कभी हर महीने आने वाला बिजली का अधिक बिल उनके परिवार के बजट पर अतिरिक्त बोझ डालता था, लेकिन अब घर की छत पर लगा सोलर पैनल न केवल उनकी बिजली की जरूरत पूरी कर रहा है, बल्कि आर्थिक लाभ का माध्यम भी बन गया है। श्री आत्माराम साहू ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल स्थापित कराया है। इसके लिए उन्हें केन्द्र सरकार से 78 हजार रुपये और राज्य सरकार से 30 हजार रुपये, इस प्रकार कुल 1 लाख 8 हजार रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई। शासन की इस सहायता से उनका घर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है।

श्री साहू ने बताया कि पहले हर महीने बिजली का अधिक बिल आने से परिवार के बजट पर असर पड़ता था। बिजली बिल जमा करने की चिंता बनी रहती थी, लेकिन सोलर पैनल लगने के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई है। अब उनके घर की जरूरत से अधिक बिजली का उत्पादन हो रहा है। अतिरिक्त बिजली विद्युत ग्रिड में भेजी जा रही है, जिससे उनके बिजली खाते में क्रेडिट बढ़ रहा है और बिजली बिल शून्य अथवा माइनस में आ रहा है।उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा से घर की बिजली जरूरतें पूरी होने के साथ ही पैसों की बचत भी हो रही है। पहले जहां बिजली बिल परिवार के लिए आर्थिक बोझ था, वहीं अब अतिरिक्त बिजली उत्पादन से आर्थिक लाभ मिल रहा है। यह बदलाव उनके परिवार के लिए बड़ी राहत और खुशी लेकर आया है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर एक कॉल से दूर हुआ गांव का अंधेरा

रायपुर। सुकमा जिले के कोकावाड़ा (जांगड़पाल) गांव के लोगों को वर्षों से अंधेरे में आवाजाही की परेशानी से महज एक फोन कॉल ग्रामवासियों के लिए राहत की सौगात लेकर आया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर समस्या दर्ज कराने के बाद तत्काल मामले को संज्ञान में लाकर कार्यवाही प्रारंभ की गयी और सात दिनों के भीतर पुसपाल-चितलनार मार्ग पर स्ट्रीट लाइटें लगा दी गईं। इससे करीब 450 की आबादी वाले इस गांव के लोगों की रात में आवाजाही आसान हो गई है।

छिंदगढ़ विकासखंड के पुसपाल-चितलनार मार्ग पर स्ट्रीट लाइट नहीं होने से ग्रामीणों को रात में टॉर्च और वाहनों की हेडलाइट के सहारे आना-जाना पड़ता था। घने जंगलों से घिरे इस रास्ते पर सांप-बिच्छुओं का डर बना रहता था। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और आपात स्थिति में मरीजों को लाने-ले जाने में परेशानी होती थी।

गांव के युवा श्री रितेश यादव ने इस समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर अपनी यह समस्या दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। कलेक्टर श्री अमित कुमार की निगरानी में सात दिनों के भीतर मार्ग पर स्ट्रीट लाइटें लगा दी गईं। अब सड़क पर रोशनी होने से ग्रामीणों को रात में आने-जाने में राहत मिली है।

नवजात की मौत के मामले में पांच सदस्यीय जांच टीम ने दर्ज किए परिजनों के बयान

220 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में प्रसव के बाद बिगड़ी थी नवजात की हालत, रायपुर में उपचार के दौरान हुई मौत; परिजनों ने की निष्पक्ष जांच की मांग

महेंद्र शुक्ला ➤ एमसीबी/मनेंद्रगढ़

एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ स्थित 220 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में प्रसव के बाद नवजात शिशु की मौत के मामले में जांच शुरू हो गई है। परिजनों की शिकायत पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. अविनाश खरे द्वारा गठित पांच सदस्यीय जांच दल ने आज पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर उनके बयान दर्ज किए और मामले से जुड़े तथ्यों की जानकारी ली। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

अंबिकापुर से रायपुर रेफर किया गया था नवजात

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मनेंद्रगढ़ के लालपुर निवासी आमटी कुमार रवि ने 10 सितंबर 2026 को अपनी पत्नी



को प्रसव के लिए 220 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में भर्ती कराया था। परिजनों के मुताबिक, प्रसव के बाद अस्पताल में उन्हें बताया गया कि नवजात ने पानी पी लिया है। इसके बाद बच्चे को बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर किया गया।



परिजनों का आरोप है कि अंबिकापुर में जांच के दौरान एक्स-रे में नवजात के दोनों पैरों और हाथ की हड्डियों में फ्रैक्चर होने की बात सामने आई। इसके बाद बच्चे को रायपुर स्थित मेकाहारा अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान 4 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई।

अस्पताल प्रबंधन और थाने में की शिकायत

नवजात की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की। परिजनों ने उपचार के दौरान हुई घटनाओं की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी तय करने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग उठाई है।

पांच सदस्यीय टीम ने शुरू की जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएचएमओ डॉ. अविनाश खरे ने डॉक्टरों की पांच सदस्यीय जांच टीम गठित की है। जांच दल ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर परिजनों की शिकायत सुनी और मामले से संबंधित जानकारी जुटाई। अब जांच में सामने आने वाले तथ्यों और चिकित्सकीय अभिलेखों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

220 बिस्तरीय सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉ. स्वप्निल तिवारी के अनुसार, मामले की जांच की जा रही है।

सेवा सेतु पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण आयोजित

900 से अधिक शासकीय सेवाओं का लाभ आम नागरिकों तक सुगमता से पहुंचाने पर जोर

एक सत बुलेटिन ➤ गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

आम नागरिकों को शासकीय सेवाओं का लाभ सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुधवार को कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में सेवा सेतु पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकेश रावटे की अध्यक्षता में आयोजित प्रशिक्षण में जिले के सभी सेवा सेतु प्रबंधकों एवं अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के संचालकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध 900 से अधिक शासकीय सेवाओं, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, सेवा प्रदायगी एवं आवेदनों के समयबद्ध निराकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रावटे ने सेवा केंद्र संचालकों को निर्देशित किया कि वे नागरिकों को शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं की समुचित



जानकारी देने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन में आवश्यक सहयोग प्रदान करें। उन्होंने विशेष रूप से दूरस्थ ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों के नागरिकों तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया, ताकि लोगों को शासकीय सेवाओं के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। प्रशिक्षण में ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर श्री घनश्याम शर्मा द्वारा पोर्टल के तकनीकी पहलुओं एवं ऑनलाइन सेवाओं के संचालन की जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य सेवा केंद्र संचालकों की कार्यक्षमता बढ़ाने, डिजिटल सेवा वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा शासन की जनहितकारी सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।

महतारी वंदन योजना मांझापारा की बिराजो के ईलाज के लिए बनी सहारा

संवाददाता ➤ रायपुर

एक छोटी सी मदद जरूरतमंद के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है इसका जीवंत उदाहरण हैं श्रीमती बिराजो देवी। अपने उम्र के कारण घुटनों के दर्द से परेशान रहने वाली बिराजों को महतारी वंदन की राशि ने अपने इलाज का संबल दे दिया है। कोरिया जिले के ग्राम पंचायत खरवत के आश्रित ग्राम मांझापारा में रहने वाली बिराजो के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव भैय्या की महतारी वंदन योजना एक जबरदस्त मदद साबित हो रही है।बढ़ती उम्र में अपने घुटनों के दर्द से परेशान रहने वाली बिराजो देवी के लिए हर समय इलाज में लगने वाला खर्च उनके लिए एक कठिन चुनौती था। जब कभी घर वाले दिखला कर दवा ला देते तब तक ठीक था लेकिन जब वह दवा नहीं लाते तब बिराजो को अपना दर्द खुद सहना पड़ता। ऐसे कठिन



समय में महतारी वंदन से मिलने वाली रकम ने बिराजों के दर्द का इलाज कर दिया हैंअब वह अपने घुटनों के इलाज में होने वाले खर्च के लिए किसी पर आश्रित नहीं है। मुस्कुराते हुए उनहोने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद देकर कहा कि उनके घुटनों की दवाई का इंतजाम हो गया है और वह किसी पर आश्रित नहीं हैं।

पत्नी और बच्चों के साथ सुरक्षित घर में रहने का मिला सुकून, बेहतर भविष्य की उम्मीदों को मिले नए पंख

प्रधानमंत्री आवास योजना से नवेद के परिवार का पक्के घर का सपना हुआ साकार, खुशियों से रोशन हुआ आशियाना

सेवा संकल्प अभियान- सेवा की कहानी - प्रधानमंत्री आवास योजना से नवेद के परिवार का पक्के घर का सपना हुआ साकार, खुशियों से रोशन हुआ आशियाना

पक्की छत से परिवार को मिली सुरक्षा और सम्मान, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति जताया आभार

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना एक पक्का घर हो, जहां वह परिवार के साथ सुरक्षित, सम्मानजनक और सुकून भरा जीवन बिता सके। विशेषकर बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एक सुरक्षित आशियाना परिवार की सबसे बड़ी जरूरतों में शामिल होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) जरूरतमंद परिवारों के इसी सपने को साकार करने का माध्यम बन रही है। जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत अमरताल निवासी श्री नवेद कुमार मनहर के जीवन में भी इस योजना से खुशियों का नया अध्याय जुड़ा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिलने से अब उनका परिवार सुरक्षित वातावरण में बेहतर जीवन की ओर आगे बढ़ रहा है। 'पत्नी और बच्चों के लिए सुरक्षित आशियाना बना खुशियों का आधार' श्री नवेद कुमार मनहर के परिवार में उनकी पत्नी और बच्चे हैं। परिवार की जिम्मेदारियों के बीच अपने घर



का सपना पूरा होना उनके लिए विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मिला पक्का मकान अब उनके परिवार की सुरक्षा और बेहतर रहन-सहन का आधार बन गया है। पक्की छत होने से परिवार को धूप, बारिश और मौसम की अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव मिल रहा है। साथ ही बच्चों को सुरक्षित वातावरण और परिवार को दैनिक जीवन में अधिक सुविधा प्राप्त हो रही है। नवेद कुमार के लिए यह आवास केवल ईंट और सीमेंट से बना मकान नहीं, बल्कि परिवार के सपनों, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की उम्मीदों से जुड़ा अपना आशियाना है। पक्का घर मिलने से परिवार को स्थायित्व और सुकून मिला है। अब वे अपने बच्चों के भविष्य और परिवार की खुशहाली को लेकर अधिक विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं।'पक्की छत के साथ मिला सम्मानजनक जीवन का आधार'प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पात्र ग्रामीण परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित आवासीय सुविधा प्रदान करना है, ताकि वे बेहतर और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।

केल्हारी के नवीन थाना भवन का विधायक रेणुका सिंह ने किया लोकार्पण

आईजी दीपक कुमार झा और एसपी रत्ना सिंह सहित जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक रहे मौजूद

एक सत बुलेटिन ➤ केल्हारी/एमसीबी

जिला एमसीबी के थाना केल्हारी को बुधवार को नवीन थाना भवन की सौगात मिली। भरतपुर-सोनहत विधायक एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह ने नवीन थाना भवन का फीता काटकर विधिवत लोकार्पण किया। कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज श्री दीपक कुमार झा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

नवीन थाना भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक एमसीबी श्रीमती रत्ना सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती यशवंती सिंह, जनपद उपाध्यक्ष मनेन्द्रगढ़ श्रीमती ज्योति गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती अनीता सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

लोकार्पण के पश्चात अतिथियों ने नवीन थाना भवन का निरीक्षण किया। भवन में उपलब्ध



आवश्यक सुविधाओं का जायजा लिया गया। नवीन थाना भवन के शुरू होने से पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलने के साथ ही आम नागरिकों को भी पुलिस संबंधी कार्यों के लिए सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध होने की उम्मीद है।

इस अवसर पर नवीन थाना भवन को क्षेत्र की कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने तथा पुलिस एवं आम जनता के बीच समन्वय मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया। नए भवन से पुलिसकर्मियों में नई ऊर्जा का संचार होने और क्षेत्र में पुलिसिंग व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई गई।

बिहान योजना और नाबार्ड के प्रशिक्षण से निखरा हुनर, घर बैठे पैरा आर्ट से अर्जित कर रहीं अच्छी आमदनी

सेवा संकल्प अभियान : सेवा की कहानी : धान के पैरे से धनेश्वरी ने गढ़ी आत्मनिर्भरता की नई पहचान, कला को बनाया कमाई का जरिया

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

खेतों में धान की कटाई के बाद बचने वाला पैरा भी किसी के जीवन में खुशहाली और आत्मनिर्भरता का माध्यम बन सकता है। जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम अवरीद निवासी श्रीमती धनेश्वरी धीवर ने अपनी मेहनत, लगन और रचनात्मकता से इसे सच कर दिखाया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' से जुड़कर उन्होंने पैरा आर्ट की कला सीखी और आज इसी हुनर के बल पर घर बैठे अच्छी आमदनी अर्जित कर रही हैं। कभी केवल अपनी रुचि के लिए सीखी गई कला अब उनकी आजीविका का आधार बन गई है। इतना ही नहीं, धनेश्वरी अब दूसरों को भी पैरा आर्ट का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

बिहान से मिला अवसर, नाबार्ड के प्रशिक्षण ने संवारा हुनर

श्रीमती धनेश्वरी धीवर की आत्मनिर्भरता की यात्रा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' से जुड़ने के बाद शुरू हुई। नाबार्ड के सहयोग से उन्हें पैरा आर्ट का प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिला। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने पैरे से आकर्षक कलाकृतियां



तैयार करने की बारीकियां सीखीं। अपनी रुचि और निरंतर अभ्यास के माध्यम से उन्होंने इस कला में दक्षता हासिल की। धीरे-धीरे उनका हुनर निखरता गया और उन्होंने पैरा आर्ट को स्वरोजगार के रूप में अपनाने का निर्णय लिया।

आज धनेश्वरी घर पर ही पैरा आर्ट की कलाकृतियां तैयार कर रही हैं और उनसे अच्छी आमदनी अर्जित कर रही हैं। इस कार्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्हें रोजगार के लिए घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे घरेलू जिम्मेदारियों के साथ अपनी कला को समय देकर आय अर्जित कर पा रही हैं। इससे परिवार की आर्थिक जरूरतों में योगदान देने के साथ उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है।

अपने हुनर से दूसरों के सपनों को भी दे रहीं आकार

धनेश्वरी धीवर की सफलता केवल स्वयं तक सीमित नहीं है। पैरा आर्ट में दक्षता हासिल करने के बाद वे अब प्रशिक्षक की भूमिका भी निभा रही हैं। वे अन्य लोगों को पैरा आर्ट की तकनीक और कलाकृतियां तैयार करने का प्रशिक्षण दे रही हैं, ताकि वे भी इस कला को सीखकर स्वरोजगार के अवसर विकसित कर सकें। इस तरह उनका हुनर न केवल उनकी अपनी आजीविका का माध्यम बना है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार की संभावनाएं तैयार कर रहा है।

'सेवा संकल्प अभियान: सेवा की कहानी' : 'सरकारी सेवाओं की राह हुई आसान, सेवा सेतु से नंद किशोर की बेटी को सिर्फ 4 दिनों में मिले तीन प्रमाण पत्र'

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवाओं को सरल, सुगम और समयबद्ध बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का लाभ आम नागरिकों तक पहुंच रहा है। सेवा सेतु केन्द्रों के माध्यम से अब जरूरी प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक हो रही है। जांजगीर-चांपा जिले के सारागांव तहसील अंतर्गत ग्राम सरवानी निवासी श्री नंद किशोर का अनुभव इसका उदाहरण है। उन्होंने अपनी पुत्री के आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सेवा सेतु केन्द्र में आवेदन किया और मात्र चार दिनों के भीतर तीनों प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए। प्रमाण पत्रों की डिजिटल प्रतियां सीधे उनके मोबाइल पर उपलब्ध होने के साथ ही हार्ड कॉपी भी प्रदान की गई।

'चार दिनों में पूरे हुए तीन काम, मोबाइल पर मिले प्रमाण पत्र'

श्री नंद किशोर अपनी पुत्री के लिए आवश्यक आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने तहसील कार्यालय स्थित सेवा सेतु केन्द्र में आवेदन किया। केन्द्र में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन स्वीकार कर आवश्यक कार्रवाई की गई। आवेदन करने के महज चार दिनों के भीतर तीनों प्रमाण पत्र तैयार हो गए और उनकी पीडीएफ प्रतियां नंद किशोर के मोबाइल पर प्राप्त हो गईं। इसके साथ ही उन्हें प्रमाण पत्रों की हार्ड कॉपी भी



उपलब्ध करा दी गई। श्री नंद किशोर के लिए यह सुविधा राहत देने वाली साबित हुई। एक ही केन्द्र के माध्यम से तीनों आवश्यक दस्तावेज समय पर प्राप्त होने से उन्हें अलग-अलग प्रक्रियाओं की परेशानी नहीं उठानी पड़ी। डिजिटल माध्यम से प्रमाण पत्र उपलब्ध होने के कारण दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया भी सुविधाजनक रही। 'न कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर, न लंबा इंतजार'सेवा सेतु केन्द्र से समय पर प्रमाण पत्र मिलने पर श्री नंद किशोर ने प्रसन्नता व्यक्त की।

न्यूज इन शॉर्ट

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए चौथी ओपन काउंसलिंग 16 अक्टूबर को

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही,मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजनांतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालयों की तर्ज पर संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु चतुर्थ ओपन काउंसलिंग का आयोजन 16 अक्टूबर शुक्रवार को किया गया है। यह काउंसलिंग 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित होने के पश्चात विभागीय / पर उपलब्ध रिक्त सीटों के आधार पर चतुर्थ ओपन काउंसलिंग की तिथि निर्धारित की गई है।निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काउंसलिंग सुबह 10.30 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नया रायपुर में आयोजित होगा। काउंसलिंग का स्थान इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नबर ब्लाक 5 तृतीय तल हॉल नं. 4 है। काउंसलिंग में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को कक्षा 8वीं की अंकसूची, पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी नक्सल पीड़ित प्रमाण पत्र (जहां लागू हो), निर्धारित प्रारूप में आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा विशेष श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज साथ लाने होंगे। दिव्यांग, अनाथ, विधवा माता की संतान तथा अन्य निर्धारित विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

काउंसलिंग के पश्चात प्रवेश की पात्रता होने पर संबंधित प्रयास आवासीय विद्यालय में दो दिवस के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी से काउंटर हस्ताक्षरित स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) तथा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी सिकलसेल जांच प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। रिक्त सीटों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी भी हो सकती है। विभाग द्वारा पात्र विद्यार्थियों से निर्धारित तिथि एवं समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ काउंसलिंग में उपस्थित होने की अपील की गई है, ताकि प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके।



स्वच्छता पखवाड़ा में स्वच्छता को दैनिक कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाने का संकल्प

रायपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर रेल मंडल में 01 से 15 अक्टूबर 2026 तक आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा-2026 के दौरान विभिन्न चरणों में स्वच्छता, जागरूकता, कचरा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गतिविधियां आयोजित की गईं।

रायपुर मंडल के अंतर्गत दुर्ग रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। अभियान में वरिष्ठ कोचिंग डिपो अधिकारी- दुर्ग सहित रेलवे अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लेकर स्वच्छता अभियान में अपनी भागीदारी दी। अभियान के अंतर्गत दुर्ग रेलवे स्टेशन के साथ-साथ कोचिंग डिपो, दुर्ग में भी विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालयों, कोचिंग डिपो परिसर तथा अन्य यात्री सुविधा एवं कार्यस्थल क्षेत्रों में साफ-सफाई की गई। रेलवे परिसर को स्वच्छ, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।

अभियान के दौरान कचरे के उचित निस्तारण, रेलवे परिसर में गंदगी नहीं फैलाने तथा स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। साथ ही, रेलवे कर्मचारियों एवं यात्रियों से रेलवे परिसर और कोचिंग डिपो में स्वच्छता बनाए रखने तथा इस कार्य में सक्रिय सहयोग देने की अपील की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को स्वच्छ एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना, रेलवे कर्मचारियों के कार्यस्थल को स्वच्छ रखना तथा स्वच्छता को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना रहा।

नगर पालिका अध्यक्ष ने संभाला मोर्चा

इस वर्ष जनमहोत्सव समिति करेगी रावण दहन कालेज मैदान में होगा भव्य कार्यक्रम

एक सत बुलेटिन ➤ डोंगरगांव



नगर के कालेज मैदान में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दशहरा उत्सव का आयोजन होगा. इस वर्ष जनमहोत्सव समिति डोंगरगाँव एवं नगर पालिका के संयुक्त तत्वावधान में 20 अक्टूबर विजयादशमी के दिन किया जाना है. इस वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही रामलीला का मंचन होगा, साथ ही नगर में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वालों का सम्मान होगा.आयोजन के संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष अंजू त्रिपाठी ने महत्वपूर्ण तथ्यों को सामने रखते हुए बताया कि इस वर्ष 20 अक्टूबर को सिद्धी विनायक गणेश परिवार एवं जनसहयोग से नगर के कालेज मैदान में 51 फीट रावण दहन का कार्यक्रम होगा, वहीं आने वाले वर्षों में यह पूरा कार्यक्रम डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनसहयोग मैदान में किया जायेगा. उन्होंने आगे बताया कि इस वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम लोक मंजरी रायपुर की प्रस्तुति होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार डेविड निराला, अभिषेक सोनकर, गरिमा ठाकुर, कामता वैष्णव तथा निरंजन साहू की शानदार प्रस्तुति होगी. आगामी वर्षों में नगर का दशहरा महोत्सव दो दिवसीय करने की तैयारी है, जिसकी रूपरेखा भी अभी से तैयार की जा रही है. दशहरा मैदान में निरीक्षण करने पहुंची श्रीमती त्रिपाठी के साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष दीना पटेल, मंडी अध्यक्ष रामकुमार गुप्ता, एल्डरमेन गुलशन हिरवानी, पार्षद लक्ष्मीनारायण सेन, कोमल साहू, पुरषोत्तम साहू, प्रफुल्ल जैन राजा, दुर्गेश रामटेके, पद्मिनी ठाकुर, गायत्री यादव, हेमन्त चोपड़ा, संतोष यादव सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे. इस दौरान रामकुमार गुप्ता ने बताया कि कालेज मैदान में रावण दहन के लिए शहर के समस्त दुर्गा पंडालों में आमंत्रण भेजा जा रहा है, वहीं इस वर्ष का आयोजन पूर्ववत ही रहेगा. समिति के व्दारा इस वर्ष प्रयास रहेगा कि रावण दहन का कार्यक्रम समय पर किया जा सके. वहीं सभी के सहयोग से सांस्कृतिक कार्यक्रम लोकमंजरी संध्या 7 बजे प्रारंभ हो जायेगा.

निशांत उत्सव समिति ने आयोजन खींचा हाथ =

नगर में कई वर्षों से दशहरा का कार्यक्रम निशांत उत्सव समिति के व्दारा संचालित किया जाता रहा था किन्तु इस वर्ष इस आयोजन से ऐन वक्त पर अपना पल्ला झाड़ लिया वहीं इसकी सूचना पत्र के माध्यम से नगर पालिका अध्यक्ष को दी गई थी, जिसके बाद आनन फानन में नगर पालिका परिषद सहित नगरवासियों के सहयोग से समिति का गठन कर दशहरा उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया. कार्यक्रम का भार संभालने वाले उत्सव समिति के व्दारा ऐन मौके पर लिए गए इस निर्णय के चलते दशहरा उत्सव कार्यक्रम पर ग्रहण स्थिति बन गई थी लेकिन मौके की नजाकत को देखते हुए नगर अध्यक्ष ने मोर्चा संभाला और जनसहयोग से इस पारंपरिक महोत्सव को कराने की बात कही. श्रीमती त्रिपाठी के आव्हान पर नगरवासी भी उनका साथ देने से पीछे नहीं हट रहे हैं. इधर शहर में निशांत उत्सव समिति के व्दारा लिए गए इस निर्णय की चर्चा जोरों पर है.

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर 16 अक्टूबर को युवा उत्सव का आयोजन

एक सत बुलेटिन ➤ गौरेला-पेंड्रा-मरवाही



छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राज्य के युवाओं को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत ङ्घ 2047 के विजन तथा विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प से जोड़ने के उद्देश्य से 16 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से युवा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम शासकीय मल्टीपरपज सभागार, पेंड्रा में आयोजित होगा।

कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. के निर्देशानुसार कार्यक्रम की तैयारियों एवं सफल आयोजन के लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कार्यक्रम में युवाओं की प्रतिभा, कला, साहित्य, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस अवसर पर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों तथा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले युवाओं का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य गीत की प्रस्तुति, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य-नाटिका एवं युवा संवाद का आयोजन होगा। साथ ही युवाओं को राज्य के विकास, उपलब्धियों और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में उनकी भूमिका से अवगत कराया जाएगा। कार्यक्रम में लगभग 200 विद्यार्थियों एवं युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को कार्यक्रम की सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने तथा आपसी समन्वय से आयोजन को सफल बनाने के निर्देश दिए हैं।

जिला अस्पताल में टाइप-1 डायबिटीज क्लिनिक का शुभारंभ, 6 बच्चों को वितरित की

कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने बच्चों को डाइट चार्ट का पालन करने की दी समझाइश, चिरायु टीम को चिन्हांकित बच्चों की जांच के निर्देश

एक सत बुलेटिन ➤ सारंगढ़-बिलाईगढ़





जिला अस्पताल सारंगढ़ में टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से टाइप-1 डायबिटीज क्लिनिक का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पाण्डेय एवं कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान 6 बच्चों को डायबिटीज किट वितरित की गई तथा उन्हें स्वस्थ जीवनशैली के लिए डाइट चार्ट भी प्रदान किया गया।

कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने बच्चों एवं उनके परिजनों से चर्चा करते हुए डाइट चार्ट का नियमित रूप से पालन करने की समझाइश दी। उन्होंने कहा कि नियमित स्वास्थ्य जांच, संतुलित आहार एवं चिकित्सकों की सलाह का पालन करना आवश्यक है। कलेक्टर ने संबंधित चिकित्सकों को जिले में टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों की पहचान कर उन्हें आवश्यक जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने चिरायु टीम को भी निर्देशित किया कि जिले में चिन्हांकित बच्चों की स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित की जाए, ताकि समय पर आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जा सके।

कलेक्टर ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण

क्लिनिक के शुभारंभ के बाद कलेक्टर ने जिला अस्पताल के विभिन्न वार्डों एवं व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने पुरुष वार्ड, महिला वार्ड, आपातकालीन कक्ष, ड्रेसिंग रूम एवं इंजेक्शन रूम का जायजा लिया और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की जानकारी प्राप्त की।

महिला वार्ड में भर्ती मरीजों से सीधे बातचीत कर कलेक्टर ने उपचार, दवाइयों की उपलब्धता एवं अस्पताल में मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने मरीजों को समय पर बेहतर उपचार एवं आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अस्पताल की कैंटीन का भी अवलोकन किया। उन्होंने कैंटीन संचालक को मरीजों एवं उनके परिजनों की सुविधा के लिए कैंटीन में टेबल और कुर्सियों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

सेवा संकल्प अभियान 2026: दिव्यांगजनों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने विशेष शिविर आयोजित

रायपुर,दिव्यांगजनों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने विशेष शिविर आयोजित मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिव्यांगजनों को शासकीय योजनाओं और सेवाओं का लाभ सुलभ कराने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सेवा संकल्प अभियान 2026 के अंतर्गत श्सेवा मेरा योगदानश् पहल के तहत जशपुर जिले के फरसाबहार में दिव्यांगजन सेवा संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दिव्यांगजनों को प्रमाण-पत्र एवं विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ सामाजिक सुरक्षा, सहायक उपकरण और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं का लाभ दिलाने की पहल की गई।

दिव्यांगजनों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने विशेष शिविर आयोजित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरसाबहार में आयोजित शिविर में कुल 145 दिव्यांगजन उपस्थित हुए। इनमें से 63 दिव्यांगजन यूडीआईडी कार्ड के लिए पात्र पाए गए, जबकि 11 दिव्यांगजनों को विशेष चिकित्सकीय परीक्षण एवं आवश्यक जांच के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया। शिविर में पात्र दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र भी वितरित किए गए।दिव्यांगजनों को एक ही स्थान पर मिली विभिन्न योजनाओं की सुविधा शिविर में दिव्यांगता प्रमाणीकरण एवं यूडीआईडी कार्ड से संबंधित कार्यों के साथ दिव्यांगजनों की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पेंशन योजनाओं, सहायक उपकरणों और दिव्यांग ऋण योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त किए गए।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उपस्थित हितग्राहियों को योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में मार्गदर्शन भी प्रदान किया। यूडीआईडी कार्ड के माध्यम से दिव्यांगजनों को अपनी पहचान और दिव्यांगता संबंधी जानकारी का एकीकृत दस्तावेज उपलब्ध होता है, जिससे विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान होती है। वहीं सहायक उपकरणों और स्वरोजगार ऋण से संबंधित योजनाएं दिव्यांगजनों की दैनिक गतिविधियों में सुविधा तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में सहायक हैं।

दिव्यांगजनों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में पहल सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित इस विशेष शिविर का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आवश्यक प्रमाण-पत्रों और शासकीय योजनाओं से जोड़ने के साथ उन्हें सामाजिक सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता के अवसर उपलब्ध कराना है। स्थानीय स्तर पर शिविर आयोजित होने से दिव्यांगजनों को विभिन्न सेवाओं के लिए अलग-अलग कार्यालयों में जाने की परेशानी कम होती है और उन्हें एक ही स्थान पर आवश्यक जानकारी एवं सुविधाएं मिलती हैं।

शिविर में जनपद पंचायत फरसाबहार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मिथलेश पैंकरा सहित समाज कल्याण विभाग एवं जनपद पंचायत के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। विभागीय अमले ने दिव्यांगजनों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करते हुए प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया सुनिश्चित की।

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ.ग.)

दूरभाष क्र.– 07751 220658 Email – actwd.gpm@gmail.com

//ई–निविदा आमंत्रण सूचना//

कमांक/ LAND/3/2026-O/O ASSTT COMMER (TRIBAL) 2134 #Approved Date# 12/10/2026

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की ओर से लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ में पंजीकृत ठेकेदारों से लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी अनुसूची दर पुस्तिका छ0ग0 शासन रायपुर दिनांक 01.01.2015 एवं संशोधित दिनांक 04.05.2018 तक लागू एवं विद्युतीकरण दर अनुसूची जो दिनांक 01.07.2015 से प्रभावशील है, (समस्त संशोधन सहित) एस.ओ.आर. पद्धति के तहत ई–टेंडरिंग के माध्यम से प्रतिशत दर पर निविदा आमंत्रित किया जाता है।

01. ई–निविदा प्रारम्भ तिथि – 13.10.2026
02. निविदा की अंतिम तिथि – 03.11.2026 (सायंकाल 5:30 बजे तक)
03. निविदा खोलने की तिथि – 05.11.2026 (प्रातः 11:00 बजे)

क्र.	संस्था/कार्य का नाम	प्रति इकाई लागत राशि (लाखों में)	प्रति इकाई अमानत राशि
01	17 छात्रावास/आश्रमों में डुप्लेक्स/अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य (प्रथम तल)	11.82	12000.00

नोटः–
1. कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह।
2. ठेकेदार का श्रेणी "डी" क्लास या उससे ऊपर।

टीप :–निविदा की शर्ते व अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.inमें देखी जा सकती है।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही छ0ग0

262704002/3

**OFFICE OF THE SUPERINETENDING ENGINEER
PUBLIC WORK DEPARTMENT, BILASPUR CIRCLE
BILASPUR, CHHATTISGARH**

निविदा निरस्तीकरण सूचना

इस कार्यालय के निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 251 दिनांक 27.08.2026 एवं 308 दिनांक 18.09.2026 को अपेन्डिक्स 2.10 की कंडिका 4.6 के तहत् अपरिहार्य कारणवश निरस्त किया जाता है।

अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग
बिलासपुर मण्डल, बिलासपुर

पृ. क्रमांक 2797/सा./20– 262704010/4

बिलासपुर, दिनांक 14/10/26

उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात की तैयारी करने पर दिया जोर

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा से मिलीं माँ दंतेश्वरी महिला किसान उत्पादक कंपनी की सदस्य, उप मुख्यमंत्री ने एनपीओपी प्रमाणन मिलने पर दी बधाई

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर



उप मुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा से आज दंतेवाड़ा सर्किट हाउस में माँ दंतेश्वरी महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड की पदाधिकारियों एवं महिला सदस्यों ने मुलाकात की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कंपनी को वनोपज के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के अंतर्गत जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त होने पर महिलाओं को बधाई दी। मुलाकात के दौरान महिला सदस्यों ने उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा को अपनी कंपनी के 'दण्डक ब्रांड' का चावल का पैकेट भेंट किया। श्री शर्मा ने महिलाओं से कंपनी की गतिविधियों, उत्पादों की बिक्री, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और बाजार की संभावनाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की।

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा से मिलीं माँ दंतेश्वरी महिला किसान उत्पादक कंपनी की सदस्य

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि एनपीओपी प्रमाणन मिलने के बाद अब दण्डक ब्रांड के उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। इस दौरान उन्होंने दण्डक ब्रांड को छत्तीसगढ़ के 'छत्तीसकला' ब्रांड के साथ जोड़कर व्यापक बाजार उपलब्ध कराने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने महिलाओं से उत्पादों की गुणवत्ता, आकर्षक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ ही विदेशों में निर्यात के लिए आवश्यक तैयारियां करने को कहा। श्री शर्मा ने कहा कि बस्तर के प्राकृतिक वनोपज की अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अच्छी संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं का लाभ स्थानीय महिलाओं और वनोपज संग्राहकों तक पहुंचना चाहिए।

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा से मिलीं माँ दंतेश्वरी महिला किसान उत्पादक कंपनी की सदस्य

श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार बस्तर के विकास के लिए स्थानीय संसाधनों पर आधारित आजीविका को बढ़ावा दे रही है। माँ दंतेश्वरी महिला किसान उत्पादक कंपनी की उपलब्धि इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

न्यूज इन शॉर्ट

त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई

एक सत बुलेटिन य गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. के निर्देशानुसार जिले में आम नागरिकों को सुरक्षित, शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की लगातार जांच की जा रही है। इसी क्रम में नवरात्रि पर्व एवं त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए बुधवार को अभिहित अधिकारी के मार्गदर्शन में गौरेला एवं पेंड्रा क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जांच एवं नमूना संग्रहण की कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गौरेला एवं पेंड्रा में दूध विक्रेताओं से दूध के नमूने एकत्रित किए। इसके अतिरिक्त शक्कर, साबूदाना एवं सूजी के नमूने भी गुणवत्ता परीक्षण के लिए लिए गए। निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारियों को प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई रखने, खाद्य पदार्थों के भंडारण एवं विक्रय में स्वच्छता तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत आवश्यक पंजीयन कराने के लिए भी निर्देशित किया गया। जिला प्रशासन द्वारा त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों की शुद्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है, ताकि आम नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जांच एवं निगरानी की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। जिला प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों से निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने तथा नागरिकों से खाद्य सामग्री खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, स्वच्छता एवं उपयोग की अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखने की अपील की है।



सेवा की कहानी - सेवा सेतु से आसान हुआ विवाह पंजीकरण, घर बैठे मिल रही डिजिटल प्रमाण-पत्र की सुविधा

रायपुर, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की डिजिटल सुशासन की पहल आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। शासकीय सेवाओं को सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाने की दिशा में शुरू किया गया श्सेवा सेतुश् पोर्टल नागरिकों के लिए सुविधाजनक माध्यम बन रहा है। अब विभिन्न शासकीय सेवाओं के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम हो रही है। नागरिक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने, आवेदन की स्थिति जानने और डिजिटल प्रमाण-पत्र प्राप्त करने जैसी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। रायगढ़ जिले के लखन लाल पटेल और नंदिनी चौधरी को डिजिटल विवाह प्रमाण-पत्र प्राप्त होना इसी व्यवस्था की उपयोगिता का उदाहरण है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा है कि शासन की सेवाएं अंतिम छोर पर रहने वाले नागरिकों तक बिना किसी अनावश्यक परेशानी के पहुंचें। इसी उद्देश्य से राज्य में डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों के लिए सेवा सेतु पोर्टल शासकीय प्रक्रियाओं को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लखन लाल और नंदिनी को मिला डिजिटल विवाह प्रमाण-पत्र रायगढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के भगवानपुर निवासी श्री लखन लाल पटेल, पिता श्री रूपनारायण पटेल और ग्राम बयांग निवासी श्रीमती नंदिनी चौधरी, पिता श्री दिलेश्वर प्रसाद चौधरी का विवाह 8 मई 2025 को संपन्न हुआ था। विवाह के बाद दंपती ने विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की। कार्यालय विवाह पंजीयक, जनपद पंचायत रायगढ़ द्वारा 14 जुलाई 2026 को उनके विवाह का पंजीकरण अनुमोदित किया गया और डिजिटल विवाह प्रमाण-पत्र जारी किया गया।



दुर्ग न्यायालय में तकनीक से सिमट रही दूरी: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जमानत आवेदन का निराकरण, मुंबई और चेन्नई के गवाहों के बयान दर्ज

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के प्रयासों से डिजिटल न्याय और विधिक जागरूकता को बढ़ावा देने की पहल

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

न्याय पाने के लिए दूरी बाधा न बने और न्यायिक प्रक्रिया समय तथा संसाधनों के लिहाज से अधिक सुगम हो - इसी उद्देश्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक जमानत आवेदन पर सुनवाई कर उसका निराकरण किया गया, वहीं मुंबई और चेन्नई में मौजूद महत्वपूर्ण गवाहों के बयान एवं प्रतिपरीक्षण की कार्यवाही भी पूरी कराई गई। यह पहल न्यायिक कार्यों में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने तथा न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है।



जब न्यायालयीन कार्यवाही में दूरी बाधा नहीं बनी

एक प्रकरण में अधिवक्ताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जमानत आवेदन पर अपना पक्ष रखा। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आवेदन का विधिवत निराकरण किया। इस व्यवस्था से अधिवक्ताओं को वर्चुअल माध्यम से कार्यवाही में भाग लेने की सुविधा मिली और आवागमन में लगने वाले समय एवं संसाधनों की बचत में सहायता मिली।

मुंबई और चेन्नई से जुड़े गवाहों के दुर्ग न्यायालय में दर्ज हुए साक्ष्य

एक अन्य विचारणाधीन प्रकरण में मुंबई और चेन्नई में निवासरत महत्वपूर्ण गवाहों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायिक कार्यवाही से जोड़ा गया। निर्धारित तकनीकी एवं विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उनके बयान दर्ज किए गए तथा प्रतिपरीक्षण की कार्यवाही पूरी कराई गई। इससे लंबी दूरी की यात्रा से जुड़ी कठिनाइयों को कम करने और साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सुविधा मिली।

डिजिटल न्याय के साथ जनजागरूकता पर भी जोर

न्यायिक प्रक्रिया में तकनीक का वास्तविक लाभ तभी व्यापक रूप से सामने आता है, जब नागरिकों और संबंधित हितधारकों को इसकी उपलब्ध सुविधाओं तथा उपयोग के तरीकों की जानकारी हो। इसी दृष्टिकोण के तहत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के. विनोद कुजूर के मार्गदर्शन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव उमेश कुमार भागवतकर के निर्देशन में प्राधिकरण द्वारा डिजिटल माध्यमों और तकनीकी संसाधनों के उपयोग के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के अंतर्गत आम नागरिकों, अधिवक्ताओं, पक्षकारों तथा अन्य संबंधित हितधारकों तक विभिन्न माध्यमों से पहुँचकर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य नागरिकों को न्यायिक एवं विधिक सेवाओं की उपलब्ध सुविधाओं से परिचित कराना, तकनीक के प्रभावी उपयोग के प्रति जागरूक बनाना तथा पात्र व्यक्तियों को विधिक सहायता और न्याय तक पहुँचने के उपलब्ध माध्यमों की जानकारी देना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग का यह प्रयास न्यायिक संस्थाओं और आम नागरिकों के बीच संवाद को मजबूत करने तथा डिजिटल न्याय व्यवस्था के लाभों को अधिकाधिक लोगों तक पहुँचाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने आज राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित निवास पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से आत्मीय भेंट कर उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर मंत्री श्री अग्रवाल ने डॉ. रमन सिंह के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, सुख-समृद्धि एवं खुशहाल जीवन की मंगलकामना की।

पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने संस्कृत के मंगलवाक्य 'जीवेत शरदः शतं' के साथ डॉ. रमन सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ईश्वर उन्हें स्वस्थ, सुदीर्घ एवं यशस्वी जीवन प्रदान करें। वे इसी प्रकार जनसेवा, समाज कल्याण और छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए निरंतर कार्य करते रहें तथा उनका स्नेह, आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन हम सभी को मिलता रहे।

मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि डॉ. रमन सिंह का लंबा राजनीतिक एवं प्रशासनिक अनुभव छत्तीसगढ़ के लिए एक महत्वपूर्ण धरोहर है। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में जनसेवा, सुशासन और प्रदेश के सर्वांगीण विकास को सदैव प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री के रूप में उनके लंबे कार्यकाल में प्रदेश के विकास को नई दिशा मिली और विभिन्न जनकल्याणकारी पहलों के माध्यम से आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए गए।



श्री अग्रवाल ने कहा कि डॉ. रमन सिंह का सरल, सहज एवं आत्मीय व्यक्तित्व तथा जनहित के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले सभी लोगों के लिए प्रेरणादायी है। उनका अनुभव, दूरदर्शिता और मार्गदर्शन प्रदेश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में वे लोकतांत्रिक परंपराओं, संसदीय मर्यादाओं एवं संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

पर्यटन मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों का अनुभव और मार्गदर्शन नई पीढ़ी के जनप्रतिनिधियों को जनसेवा के प्रति और अधिक समर्पण एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है। डॉ. रमन सिंह का स्नेह और मार्गदर्शन सदैव प्रेरणास्रोत रहा है।

श्री अग्रवाल ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि डॉ. रमन सिंह के जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। वे स्वस्थ एवं दीर्घायु रहकर छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करते रहें और प्रदेश को उनके अनुभव एवं मार्गदर्शन का लाभ निरंतर मिलता रहे।

जन्म-मृत्यु की घटना के एक वर्ष बाद भी अब जिले में हो सकेगा पंजीयन

जन्म एवं मृत्यु पंजीयन के नए प्रावधान एक अक्टूबर से प्रभावशील

कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को नए प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने दिए निर्देश

एक सत बुलेटिन ➤ गौरेला-पेंड्रा-मरवाही,

जन्म एवं मृत्यु पंजीयन की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 तथा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2026 के तहत नए प्रावधान लागू किए गए हैं। ये प्रावधान एक अक्टूबर 2026 से प्रभावशील हो गए हैं। कलेक्टर एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) श्री विजय दयाराम के. ने जिले की सभी पंजीयन इकाइयों को नए प्रावधानों की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने तथा उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नए प्रावधानों के अनुसार, जन्म या मृत्यु की घटना की सूचना एक वर्ष के बाद, लेकिन दो वर्ष के भीतर दिए जाने पर उसका पंजीयन जिला मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट अथवा संबंधित क्षेत्र के अधिकृत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापन एवं निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद जारी आदेश के आधार पर किया जा सकेगा। इसी प्रकार जन्म या मृत्यु की घटना की सूचना दो वर्ष के बाद दिए जाने पर उसका पंजीयन संबंधित क्षेत्र के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा घटना की सत्यता का सत्यापन करने तथा निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद जारी आदेश के आधार पर किया जाएगा।

कलेक्टर ने बताया कि नए प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी पंजीयन इकाइयों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जन्म एवं मृत्यु पंजीयन से संबंधित संशोधित नियमों की जानकारी आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जाए, ताकि विलंब से पंजीयन कराने वाले लोगों को निर्धारित प्रक्रिया की सही जानकारी मिल सके।



इस संबंध में जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व), तहसीलदारों, खंड चिकित्सा अधिकारियों, नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), उप संचालक जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय तथा संबंधित विभागों को भी नए प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने कहा गया है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं का समय पर पंजीयन कराएं तथा विलंबित पंजीयन की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें। इससे जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सुविधा होगी।

सेवा की कहानी : सुरही जलाशय योजना से 1,362 हेक्टेयर क्षेत्र में बढ़ी सिंचाई सुविधा, किसानों की खुशहाली को मिला नया आधार

जल संसाधन विभाग की पहल से 26 गांवों के किसानों को लाभ, नहर विस्तार एवं जीर्णोद्धार से खेती को मिला संबल



एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों की समृद्धि और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सिंचाई सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। इसी दिशा में खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के छुईखदान विकासखंड में सुरही जलाशय योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। जल संसाधन विभाग द्वारा सुरही जलाशय के पैरेट वियर की ऊंचाई बढ़ाने, सुरही नहर विस्तार के जीर्णोद्धार एवं लाइनिंग कार्य तथा नहर विस्तार के माध्यम से सिंचाई सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया है। इस महत्वपूर्ण परियोजना से 26 गांवों के किसानों को लाभ मिल रहा है और कृषि उत्पादन बढ़ाने की नई संभावनाएं विकसित हुई हैं।

'45.99 करोड़ रुपये की लागत से साकार हुई महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना'

सुरही जलाशय योजना के अंतर्गत 4,599.48 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना तथा किसानों के खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाना है। योजना के अंतर्गत नहरों के जीर्णोद्धार, लाइनिंग एवं विस्तार कार्य किए गए हैं। इससे जल वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने में मदद मिली है।

'1,362 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में वृद्धि से किसानों को लाभ'

सुरही जलाशय योजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता 6,393 हेक्टेयर है, जबकि पूर्व में 5,151 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी। परियोजना के अंतर्गत सिंचाई में हो रही 1,242 हेक्टेयर की कमी को दूर करने के साथ खरीफ फसलों के लिए अतिरिक्त 120 हेक्टेयर सिंचाई सुविधा विकसित की गई है। इस प्रकार कुल 1,362 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त रबी फसलों के लिए 244 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का प्रावधान किया गया है।

'नहरों के जीर्णोद्धार और लाइनिंग से जल प्रबंधन को मिली मजबूती'

परियोजना के अंतर्गत नहरों के जीर्णोद्धार एवं लाइनिंग कार्य से पानी के अनावश्यक रिसाव को कम करने और सिंचाई जल के प्रभावी वितरण की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। इससे नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की क्षमता बेहतर हुई है। सिंचाई सुविधा के विस्तार से किसानों को वर्षा पर निर्भरता कम करने, समय पर फसलों की बुवाई करने तथा बेहतर कृषि उत्पादन प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

'26 गांवों की कृषि अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल'

सुरही जलाशय योजना से लाभान्वित 26 गांवों में कृषि गतिविधियों को मजबूती मिल रही है। सिंचाई के लिए पानी की बेहतर उपलब्धता से किसानों को खरीफ के साथ रबी सीजन में भी खेती के अवसर प्राप्त होंगे। इससे फसल विविधीकरण, कृषि उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आय बढ़ाने की संभावनाएं मजबूत होंगी। विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार उनकी आजीविका को अधिक स्थिर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए शीघ्र जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए

जातिसूचक गाली एवं जान से मारने की धमकी के मामले में सर्व आदिवासी समाज ने की कार्रवाई की मांग

एक सत बुलेटिन ➤ गौरेला-पेंड्रा-मरवाही,

को कोटमी थाना क्षेत्र के ग्राम दमदम निवासी राकेश तिग्गा के साथ लाला गुप्ता एवं जुग्गा गुप्ता द्वारा कथित रूप से जातिसूचक गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी दिए जाने के मामले को लेकर सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने 16 अक्टूबर को कोटमी थाना पहुंचकर थाना प्रभारी से मुलाकात की।

प्रतिनिधिमंडल द्वारा मामले में पीड़ित का बयान दर्ज कराया गया तथा पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर शीघ्र कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई।

सर्व आदिवासी समाज ने स्पष्ट किया कि यदि मामले में 24 अक्टूबर 2026 तक उचित कार्रवाई नहीं होती है, तो समाज द्वारा कोटमी तिराहा पर चक्काजाम आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

इस दौरान सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग के अध्यक्ष मनीष सिंह धुर्वे, कार्यकारी अध्यक्ष गणेश भरिया, सचिव राजकुमार धुर्वे एवं ब्लॉक अध्यक्ष उमर पोर्ते सहित समाज के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।



सर्व आदिवासी समाज ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए शीघ्र जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

श्रेयस अय्यर बोले-गेंदबाजों ने प्लान पर अमल नहीं किया



एजेंसी ➤ नई दिल्ली

कप्तान श्रेयस अय्यर ने बुधवार को टीम इंडिया की हार पर कहा- भारतीय गेंदबाजों ने अपनी लाइन और लेंथ पर सही तरीके से अमल नहीं किया। यही वह जगह थी, जहां हम थोड़ा पीछे रह गए।

अय्यर ने कहा- 'जब आप 250 रन का पीछा कर रहे हों, तो आपको एक तय तरीके से आगे बढ़ना होता है। मुझे रन चेज के दौरान हमारा रुख पसंद आया।

हैदराबाद में खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज ने इंडिया को 24 रन से हराया। इससे 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबरी पर आ गई। आखिरी और निर्णायक मैच शनिवार को बेंगलुरु में खेला जाएगा।अय्यर ने वेस्टइंडीज के प्रदर्शन की तारीफ की। अय्यर ने कहा कि टीम ने अपनी योजनाओं पर अच्छी तरह अमल किया और विकेट से भी उसे थोड़ी मदद मिली।उन्होंने कहा, 'गेंद उछल रही थी और उन्होंने फील्ड का भी अच्छी तरह इस्तेमाल किया। उनका एग्जीक्यूशन बिल्कुल सही था।'अय्यर ने कहा कि आगे भी टीम का रुख वही रहेगा। उन्होंने कहा कि गेंदबाजी को लेकर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ प्लांस को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने पर फोकस करेंगे।स्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने नाबाद 102 रन बनाए। यह सीरीज के चार मैचों में उनका दूसरा शतक है। होप ने कहा कि उप्पल स्टेडियम की पिच के हिसाब से उनकी टीम का स्कोर अच्छा था।

फुटबॉल पर कब्जे के लिए गजब की भिड़ंत दिखी.



तुर्किये में चैंपियंस लीग के शुरुआती चरण में रोमांचक मुकाबला देखने को मिला. इसमें बार्सिलोना के एंथनी गॉर्डन और गालतासराय के बारीश यिलमाज के बीच फुटबॉल पर कब्जे के लिए गजब की भिड़ंत दिखी.

बुमराह न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से बाहर रह सकते हैं



एजेंसी ➤ नई दिल्ली

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज से बाहर रह सकते हैं। हालांकि वे पूरी तरह फिट हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, टीम मैनेजमेंट उन्हें वनडे के बजाय टेस्ट सीरीज के लिए तैयार रखना चाहता है।

बुमराह अहमदाबाद में टेस्ट की तैयारी शुरू कर चुके हैं। इस महीने के आखिर में उनके BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचने की संभावना है। इसके बाद वे न्यूजीलैंड रवाना हो सकते हैं। पहला टेस्ट 19 नवंबर से वेलिंगटन में शुरू होना है।टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, लंबे दौरे को देखते हुए टीम बुमराह के वर्कलोड को प्राथमिकता देना चाहती है। बुमराह को 6 नवंबर से शुरू होने वाले इंडिया, के तीसरे मुकाबले में खिलाने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है।इससे उनका वर्कलोड बढ़ाया जा सकेगा। इसके बाद 19 नवंबर से शुरू होने वाले पहले टेस्ट से पहले उन्हें पर्याप्त समय मिल सकेगा। बुमराह ने पिछले साल नवंबर में घरेलू मैदान पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी बार कोई मल्टी-डे मुकाबला खेला था।

जैसा उनकी पहली कामयाबी के बाद लग रहा था।

वैभव को क्यों रोके खड़े हैं गंभीर

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

15 साल के वैभव सूर्यवंशी तैयार हैं।।। बल्ले से धमाका करने को बेताब हैं।।। फैन्स उन्हें टीम इंडिया की जर्सी में मैदान पर फिर से उतरते देखना चाहते हैं, लेकिन गौतम गंभीर हैं कि उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका ही नहीं दे रहे! वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में वैभव का इंतजार खत्म नहीं हुआ और अब निगाहें न्यूजीलैंड सीरीज पर टिक गई हैं। आखिर गंभीर वैभव को रोक क्यों रहे हैं? क्या टीम इंडिया के इस किशोर सितारे को अभी सीनियर खिलाड़ियों के बीच रहकर अनुभव बटोरना चाहिए या गंभीर उसे बेंच पर बैठाकर उसके सुनहरे मौके गंवा रहे हैं?इस सवाल के साथ पृथ्वी शॉ की कहानी भी चर्चा में आ जाती है। शॉ ने भी कम उम्र में धमाकेदार शुरुआत से सुर्खियां बटोरी थीं, लेकिन आगे का सफर वैसा आसान नहीं रहा, जैसा उनकी पहली कामयाबी के बाद लग रहा था। तो क्या वैभव के मामले में



गंभीर कोई खास रणनीति अपना रहे हैं?

वैभव को लेकर गंभीर की रणनीति क्या है?

वैभव की चर्चा सिर्फ उनकी उम्र की वजह से नहीं है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने उन्हें कम समय में पहचान दिलाई है। यही वजह है कि फैन्स उन्हें भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में देखने के लिए बेताब हैं। लेकिन टीम में चयन और प्लेइंग इलेवन में जगह मिलना दो अलग बातें हैं। किसी खिलाड़ी को टीम में शामिल करने के बाद भी उसे मैदान पर उतारने का फैसला टीम संयोजन, उसकी भूमिका और मैच की जरूरत को ध्यान में रखकर लिया जाता है।

गंभीर के सामने भी यही चुनौती है। एक तरफ टीम को सीरीज जीतनी है, दूसरी तरफ इस खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आगे बढ़ने का अवसर देना है।

व्यापार

दुनिया तांबे के पीछे, ज्यादा पैसे देने को तैयार!

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

भारत में कॉपर की कीमत अगस्त में करीब ?1,400 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। ग्लोबल स्तर पर बढ़ती मांग और सीमित सप्लाई के बीच कॉपर बाजार में दबाव बढ़ रहा है। पावर ग्रिड, इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी और ढ्ढ डेटा सेंटर जैसे सेक्टर इसकी खपत बढ़ा रहे हैं।भारत में तांबे की कीमत अगस्त 2026 में करीब ?1,400 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। 17 अगस्त को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि। (स्ष्ठङ्क) पर कॉपर कॉन्ट्रैक्ट भी लगभग इसी स्तर पर कारोबार कर रहे थे। बाजार में सिर्फ कीमत ही नहीं बढ़ी है, बल्कि तुरंत सप्लाई हासिल करने के लिए खरीदारों को



प्रीमियम भी चुकाना पड़ रहा है।कॉपर की कीमतों में तेजी के पीछे ग्लोबल डिमांड और सप्लाई के बीच बढ़ता अंतर बड़ी वजह माना जा रहा है। पावर ग्रिड, इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी और डेटा सेंटर जैसे सेक्टर में कॉपर की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। इसी वजह से लंदन मेटल एक्सचेंज के करीब बनी हुई हैं।

एयरटेल पेमेंट्स बैंक की नई चेयरपर्सन होंगी शबनम सिन्हा

सुनील मित्तल 10 साल बाद पद छोड़ेंगे, 30 सितंबर को कंपनी के बोर्ड से हटेंगे

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

वर्ल्ड बैंक की पूर्व लीड स्पेशलिस्ट और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डॉ. शबनम सिन्हा 1 अक्टूबर 2026 से बैंक की नई चेयरपर्सन के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगी।

एयरटेल पेमेंट्स बैंक की नई चेयरपर्सन शबनम सिन्हा होंगी। वे 1 अक्टूबर 2026 से यह पद संभालेंगी। शबनम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुनील भारती मित्तल की जगह लेंगी। मित्तल 30 सितंबर को अपना 10 साल का कार्यकाल पूरा करके बोर्ड से हट जाएंगे।डॉ. शबनम सिन्हा के पास बैंकिंग, गवर्नेंस और डिजिटल बदलाव का 30 से ज्यादा सालों का ग्लोबल अनुभव है। उन्होंने 2010-2025 यानी 15 साल वर्ल्ड बैंक में बतौर लीड स्पेशलिस्ट काम किया। यहां उन्होंने एशिया, यूरोप और अफ्रीका में 4 बिलियन डॉलर यानी करीब ?38,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी संभाली।

वर्ल्ड बैंक से पहले वह ढ्ढरू स्रस् एजुकेशन की



ष्टश्वह्र रह चुकी हैं और स्रढ्ढष्ठ व ह्यष्टश्वक्रह्म के साथ भी लंबे समय तक काम कर चुकी हैं। फिलहाल वह एयरटेल पेमेंट्स बैंक, वेदांता और भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे बड़े संस्थानों के बोर्ड में शामिल हैं।शबनम सिन्हा बोली- जिम्मेदारी मिलना सम्मान की बात

डॉ. शबनम ने कहा कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक की कमान संभालना मेरे लिए गर्व की बात है, खासकर ऐसे वक्त में जब डिजिटल बैंकिंग देश की तरक्की में सबसे अहम रोल निभा रही है। बैंक ने आसान तकनीक के जरिए एक ऐसा मजबूत और भरोसेमंद जरिया तैयार किया है,।

राज्यों का आरोप है कि मेटा को पता था।

मेटा पर भारी जुर्माने का संकट

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

मेटा अब एक नए कोर्ट केस का सामना करने जा रही है, जहां जहां उसके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं. प्लेटफॉर्म पर आरोप हैं कि उसकी वजह से लोगों को सोशल मीडिया की लत लग रही है और उसके ऐप्स कई तरह के नुकसान पहुंचा जा रहे हैं।

साथ ही उसके ऐप्स की वजह से बच्चों की मेंटल हेल्थ भी प्रभावित हो रही है, जिसके कारण कंपनी को दर्जनों केस का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कंपनी को 1।4 ट्रिलियन डॉलर (करीब 133।92 लाख करोड़ रुपये) के जुर्माने तक भरना पड़ सकता है।

नए मामले की सुनवाई मंगलवार को कैलिफोर्निया के ओकलैंड स्थित संघीय अदालत में शुरू की जाएगी। बीते सप्ताह मेटा ने इस मामले को खारिज कराने की मांग की थी, लेकिन कंपनी की अर्जी को कंपनी ने



स्वीकार नहीं किया।

सीईओ मार्क जकरबर्ग को पड़ेगा पेश

इस केस के दौरान मेटा के टॉप ऑफिसर्स और कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग तक की सुनवाई हो सकती है। साथ ही कंपनी पर बहुत मोटा जुर्माना तक लगाया जा सकता है। राज्यों ने मेटा पर आरोप लगाया था कि मेटा ने जानबूझकर ऐसे फीचर्स को तैयार किया है, जो असल में यूजर्स को उसके प्लेटफॉर्म का आदि बनाते हैं।

2023 में मेटा के खिलाफ दायर केस से कनेक्ट हैं

यह मामला साल 2023 में कई अमेरिकी राज्यों की ओर से मेटा के खिलाफ दायर किए गए केस से कनेक्टेड है। यह कार्रवाई कंपनी की सुरक्षा नीतियों को लेकर कई राज्यों की जांच के बाद हुई, जिसके बाद जांच में बच्चों और किशोरों को होने वाले गंभीर नुकसान सामने आए थे। ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स में दी है।

मेटा के खिलाफ आरोप सुनेंगें

सुनवाई के दौरान जज यवोन गोंजालेज रोजर्स कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी के आरोपों को सुनेंगे, जिसमें मेटा पर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि मेटा ने अपने ऐप्स की सुरक्षा को लेकर जानबूझकर गुमराह किया और उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का उल्लंघन किया।

चार राज्यों समेत कुल 29 राज्य मेटा पर चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट के उल्लंघन के आरोप लग चुके हैं। राज्यों का आरोप है कि मेटा को पता था।

विदेश में मारुति सुजुकी फॉन्क्स की बंपर डिमांड



विदेश में मारुति सुजुकी फॉन्क्स की बंपर डिमांड

मारुति सुजुकी भारत में सबसे ज्यादा कारें बेचती है. मारुति सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि विदेशों में एक्सपोर्ट के लिए भी कई कारें बनाती है। ऐसी ही एक कार मारुति सुजुकी फॉन्क्स है, जो काफी ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही है। इस कार की 2 लाख यूनिट्स को भारत से बाहर एक्सपोर्ट किया जा चुका है। इस आंकड़े तक यानी 2 लाख एक्सपोर्ट तक मारुति सुजुकी फॉन्क्स सबसे तेजी से पहुंची है। कॉम्पैक्ट एसयूवी को यहां तक पहुंचने में 38 महीनों का वक्त लगा है। फॉन्क्स का एक्सपोर्ट जून 2023 में शुरू हुआ। फिलहाल इस मेड इन इंडिया एसयूवी को 90 देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। मारुति इस कार की मैन्युफैक्चरिंग गुजरात के हंसलपुर प्लांट में करती है।



हदों के पार महंगाई

खुदरा महंगाई ने बीते 23 माह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत सरकार के ही सांख्यिकी मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं कि सितंबर, 2026 में खुदरा महंगाई दर 5.54 फीसदी रही। यह अक्तूबर, 2024 के बाद का उच्चतम स्तर है। तब महंगाई दर 6.2 फीसदी थी। भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि आने वाले महीनों में भी महंगाई बढ़ेगी। अक्तूबर-दिसंबर की औसत महंगाई दर 6 फीसदी या उससे अधिक भी हो सकती है। केंद्रीय बैंक ने महंगाई दर की सीमा वैसे तो 4 फीसदी तय कर रखी है, लेकिन उसे 6 फीसदी तक 'सामान्य' मान कर तमाम आकलन और विश्लेषण किए जाते हैं। लगातार चौथे माह उस 'लक्ष्मण-रेखा' को लांघा गया है, क्योंकि खाद्य महंगाई दर और शहरी-ग्रामीण इलाकों में महंगाई की स्थितियां भिन्न और अधिक हैं। खाद्य महंगाई दर सितंबर में बढ़ कर 7.74 फीसदी तक पहुंच गई। गांवों में खुदरा महंगाई दर 5.24 फीसदी से बढ़ कर 6.08 फीसदी हो गई। ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई दर 8.06 फीसदी और शहरों में 7.18 फीसदी दर्ज की गई है। ये तमाम आंकड़े रिजर्व बैंक की तय हदों के पार हैं, लिहाजा साफ है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। गैर-सरकारी और पेशेवर संगठनों, संस्थानों, एजेंसियों के आंकड़े भिन्न और अपेक्षाकृत अधिक हैं। आम आदमी महंगाई के इन प्रतिशत वाले आंकड़ों का अर्थशास्त्र नहीं जानता। उसके लिए महंगाई वहीं से शुरू होती है, जब आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, नींबू, अदरक और हरी मिर्च सरीखी रोजमर्रा की सब्जियां महंगी मिलने लगती हैं। इस बाजार और भाव पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि सब्जी मंडी के व्यापारी आपस में मिल कर कीमतें तय कर लेते हैं, वहीं से खुदरा बाजार भी महंगा हो जाता है। गली-मुहल्ले के छोटे कारोबारी और रेहड़ीवाले भी उसी अनुपात में दाम बढ़ा देते हैं। तर्क दिया जाता है कि 'ऊपर' से ही भाव बढ़ गए हैं। हम क्या कर सकते हैं जी? यदि प्याज करीब 108 फीसदी और लहसुन 55 फीसदी महंगा और आलू 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, तो यह किस अर्थशास्त्र के आधार पर तय किया जाता

विचार

प्रधानमंत्री आवास योजना से साकार हो रहा गरीबों का पक्के घर का सपना

ए.बी. काशी

सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग

हर गरीब परिवार का अपना पक्का घर हो, इसी संकल्प के साथ जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं प्रधानमंत्री जनमन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। शासन की इन महत्वाकांक्षी योजनाओं से ग्रामीण अंचलों में जरूरतमंद परिवारों के पक्के मकान का सपना साकार हो रहा है। कच्चे एवं असुरक्षित मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जिले में विभिन्न वित्तीय वर्षों में कुल 56 हजार 455 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 47 हजार 19 आवास पूर्ण हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2016-18 के अंतर्गत स्वीकृत 10 हजार 797 आवासों में से 10 हजार 650 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2019-23 के अंतर्गत स्वीकृत 16 हजार 811 आवासों में से 15 हजार 234 आवास पूर्ण हुए हैं। इन दोनों अवधियों में कुल 25 हजार 884 आवासों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-26 के अंतर्गत जिले में 28 हजार 847 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 28 हजार 26 हितग्राहियों को प्रथम किस्त, 24 हजार 165 को द्वितीय किस्त तथा 17 हजार 144 हितग्राहियों को तृतीय किस्त की राशि जारी की गई है। इस अवधि में अब तक



21 हजार 115 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। शेष आवासों के निर्माण कार्यों को गति देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री आवास योजना से भी मिल रहा पक्के मकान का सहारा

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जिले में 423 आवास स्वीकृत हैं। इनमें सभी 423 हितग्राहियों को प्रथम किस्त, 298 को द्वितीय किस्त, 249 को तृतीय किस्त तथा 235 हितग्राहियों को चतुर्थ किस्त की राशि प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गत अब तक 249 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। शेष आवासों को पूर्ण कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

पीएम जनमन योजना से विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के जीवन में आ रहा बदलाव

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के परिवारों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। गौरेला विकासखंड में योजना के अंतर्गत 1080 आवास स्वीकृत हैं, जिनमें से 886 आवास पूर्ण हो चुके हैं। इस योजना से विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को पक्के मकान की सुविधा मिलने के साथ उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।

आवास निर्माण में तेजी लाने जिला प्रशासन प्रतिबद्ध

कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. के मार्गदर्शन में आवास योजनाओं की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आवास निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं, किस्तों के भुगतान तथा अपूर्ण आवासों की स्थिति की नियमित समीक्षा कर निर्माण कार्यों को गति देने पर जोर दिया जा रहा है। हितग्राहियों के आधार सत्यापन, बैंक खाते एवं तकनीकी समस्याओं के निराकरण की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना केवल पक्के मकान के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गरीब परिवारों के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और स्थायित्व का आधार भी बन रही है। पक्की छत मिलने से परिवारों को मौसम की मार से राहत मिलती है, वहीं बच्चों को बेहतर वातावरण में पढ़ाई करने तथा परिवार को सुरक्षित जीवनयापन का अवसर मिलता है। शासन की आवास योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही हैं। जिले में आवास निर्माण की यह प्रगति अंत्योदय की भावना को साकार करते हुए जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

गन्ना मूल्य में छत्तीसगढ़ देश में नंबर वन



धनंजय राठौर

सयुक्त संचालक जनसंपर्क, रायपुर

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अन्नदाता की खुशहाली ही छत्तीसगढ़ का आधार है। किसानों को उनकी मेहनत का बेहतर प्रतिफल मिले, खेती लाभकारी बने और किसान परिवार आर्थिक रूप से सशक्त हों, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री साय ने किसानों के हितों को ध्यान में रखकर शक्कर कारखानों के लिए गन्ने की खरीदी 425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से करने का निर्णय लिया है। पेराई सत्र 2025- 26 में की गई खरीदी का भुगतान भी बढ़े हुए दर पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि लागत को कम करने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार भी किसानों के हितों को अपनी नीतियों और निर्णयों के केंद्र में रखकर आगे बढ़ रही है। किसानों की आवश्यकताओं और समस्याओं के प्रति सरकार संवेदनशील है। किसान हित से जुड़े विषयों पर प्राथमिकता से निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण समृद्धि में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। खेती-किसानी मजबूत होगी तो गांव मजबूत होंगे। गांवों की समृद्धि से ही छत्तीसगढ़ की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा।

छत्तीसगढ़ सरकार ने गन्ना किसानों की आय बढ़ाने और गन्ने की खेती को लाभकारी बनाने के लिए गन्ने के खरीदी मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने गन्ने का खरीदी मूल्य 355 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 425 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया है। इस बढ़े हुए मूल्य का लाभ पेराई सत्र 2025-26 के गन्ने पर भी मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य की चार सहकारी चीनी मिलों से जुड़े 31 हजार से अधिक किसानों को लगभग 51.09 करोड़ का बोनस वितरित किया जाएगा।

राज्य सरकार ने गन्ना खरीदी दर बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल कर दी

देश के कुल गन्ना उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान भले ही कम है लेकिन गन्ना किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने में राज्य अब नंबर वन हो गया है। राज्य सरकार ने गन्ना खरीदी दर बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में लिए गए इस फैसले से छत्तीसगढ़ में गन्ने की खरीदी दर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों की तुलना में अधिक हो गई है। खास बात यह है कि बढ़ी हुई दर पेराई सत्र 2025-26 से ही लागू होगी। इस सत्र में पहले ही गन्ना बेच चुके किसानों को भी बढ़ी हुई दर के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

किसानों को प्रति क्विंटल 70 रुपये अधिक मिलेंगे

सरकार के इस फैसले का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने के साथ गन्ने की खेती को अधिक लाभकारी बनाना है।राज्य में पहले गन्ने की खरीदी 355 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होती थी। नई दर से किसानों को प्रति क्विंटल 70 रुपये अधिक मिलेंगे। गन्ना मूल्य में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई है, जब खेती की लागत और किसानों की आमदनी के बीच संतुलन बनाना कृषि नीति की प्रमुख चुनौती है।

देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में अगैती प्रजाति के गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) 400 रुपये प्रति क्विंटल, हरियाणा में 415 रुपये और पंजाब में 416 रुपये प्रति क्विंटल है। जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ने का भुगतान केंद्र सरकार के उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी), चीनी की रिकवरी और संबंधित मिलों की व्यवस्था के आधार पर निर्धारित होता है। केंद्र सरकार ने 2026-27 के लिए 10.25 प्रतिशत चीनी रिकवरी पर एफआरपी 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।

विचार

छत्तीसगढ़ की शक्तिपीठ परियोजना

धनंजय राठौर

संयुक्त संचालक, जनसंपर्क रायपुर

पर्यटन एक ऐसी यात्रा या भ्रमण है, जो मनोरंजन या फुर्सत के क्षणों का आनंद उठाने के उद्देश्य से किया जाता है। अतिथि देवो भवः भारतीय परंपरा प्राचीन काल से रही है। छत्तीसगढ़ में लगभग 138 स्थलों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के आधार पर पर्यटन स्थल के रूप में प्राथमिकता दी गई है, जिसमें 58 स्मारकों को 11 अभ्यारण 03 राष्ट्रीय उद्यान को संरक्षित घोषित किया गया है। पर्यटन मानव की प्राचीन एवं मौलिक प्रवृत्ति है। पर्यटन धरातलीय तथा मानवीय विभिन्नताओं विविधताओं का अवलोकन कर ज्ञान की बढ़ोतरी एवं मनोरंजन करता है। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यटन का एक प्रमुख गंतव्य है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर ने इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने उत्तराखंड के चार धाम की तर्ज पर राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए शक्तिपीठ परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना के तहत लगभग 1,000 किलोमीटर लंबे आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख शक्तिपीठों एवं महत्वपूर्ण पूजा स्थलों का विकास, सौंदर्याकरण तथा आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं के लिए सुगम पहुंच मार्ग, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, विश्राम स्थल एवं सुरक्षा व्यवस्था जैसी आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

छत्तीसगढ़ आस्था पथ (शक्तिपीठ भ्रमण) योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें पांचों शक्तिपीठों का भ्रमण एवं दर्शन कराया जाएगा, इसके लिए सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में 5 करोड़ का प्रावधान किया है। प्रदेश के पांच शक्तिपीठों कुदरगढ़, डोंगरगढ़, रतनपुर, चन्द्रपुर एवं दंतेवाड़ा को शक्तिपीठ सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए बजटीय प्रावधान किया है। इस परियोजना के तहत रतनपुर स्थित मां महामाया, चंद्रपुर की मां चंद्रहासनी, डोंगरगढ़ की मां बम्लेश्वरी, दंतेवाड़ा की मां दंतेश्वरी और सूरजपुर के कुदरगढ़ मंदिर को एक धार्मिक सर्किट के रूप में विकसित किया जाना था। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सरकार गठन के बाद बजट में इसके लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया था, जिससे प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को नई दिशा मिलने की उम्मीद थी। इन पाँचों शक्तिपीठों को बेहतर सड़कों, यात्री सुविधाओं, विश्राम स्थलों और सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और जिला प्रशासन द्वारा इन मंदिरों में सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का काम तेजी से किया जा रहा है।

केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले स्थित माँ महामाया मंदिर, रतनपुर के समग्र विकास के लिए 200 करोड़ की कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसे केन्द्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय को प्रेषित की गई है। उक्त कार्य योजना को स्वीकृति मिलते ही एंजेसी तय कर कार्य प्रारंभ की जाएगी। यह मंदिर 11वीं-12वीं शताब्दी के दौरान कलचुरी राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था और यह माँ महालक्ष्मी एवं माँ महासरस्वती को समर्पित है। यह दक्षिण कोशल क्षेत्र की आराध्य देवी और रतनपुर राज्य की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती हैं। इसके अलावा डोंगरगढ़, कुदरगढ़, चंद्रपुर और दंतेवाड़ा की शक्तिपीठों के लिए सीपीआर तैयार करने प्रक्रियाधीन है।

प्रसाद योजना के तहत केंद्र सरकार ने प्रथम चरण में देश के 26 धार्मिक तीर्थ स्थलों का चयन किया है। इन्हें पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जा रहा है ताकि देश-विदेश के पर्यटक यहां पहुंच सकें। पर्यटन को बढ़ावा मिले। इन स्थलों की प्रसिद्धी का विस्तार हो। हमारे प्रमुख देवी तीर्थ स्थल महामाया मंदिर और दंतेश्वरी मंदिर को प्रसाद योजना में



शामिल करवाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाकर केंद्र सरकार को भेजा गया है।

यह सुविधाएं की जानी है विकसित

पांचों शक्तिपीठों में गार्डन, ठहने की व्यवस्था, लाइटिंग, हवन-पूजन स्थल, रेलिंग, पानी, सामुदायिक शौचालय, बैठने की व्यवस्था, रोप-वे, पर्यटन मंडल का केंद्र, सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा व्यवस्था और होम स्टे आदि की सुविधाएं विकसित की जानी है। इन स्थलों में बेहतर सड़क संपर्क, स्वच्छ पेयजल, आधुनिक शौचालय, सुव्यवस्थित पार्किंग, पर्यटक सहायता केंद्र, डिजिटल सूचना प्रणाली, प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा जैसी आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता के साथ विकसित किया जाएगा। इन पर्यटन स्थलों की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए उनके विकास में स्थानीय वास्तुकला, संस्कृति और प्राकृतिक परिवेश के संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा।

1. मां बम्लेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में स्थित डोंगरगढ़ की सुरम्य पहाड़ियों की गोद में विराजी माँ बम्लेश्वरी देवी इस क्षेत्र की ही नहीं, बल्कि देश-विदेश के लाखों-करोड़ों श्रद्धालुओं की अगाध आस्था का मुख्य केंद्र हैं। समुद्र तल से लगभग 1600 फीट की ऊँचाई पर पहाड़ी पर स्थित यह पवित्र मंदिर माँ शक्ति के पावन रूपों में विशेष स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में स्थित माँ बम्लेश्वरी मंदिर का इतिहास लगभग 2200 वर्ष पुराना है। यह एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। 2200 वर्ष पहले यहाँ कामाख्या नगरी (वर्तमान डोंगरगढ़) थी, जहाँ राजा वीरसेन का शासन था। निःसंतान होने पर उन्होंने शिव और दुर्गा की आराधना की। देवी की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसके बाद उन्होंने इस मंदिर की स्थापना करवाई। 11वीं शताब्दी में कलचुरी राजा कर्णदेव ने इस मंदिर को पुनर्विकसित किया। बाद में 15वीं-16वीं शताब्दी में गोंड राजाओं ने इस क्षेत्र और मंदिर का विस्तार किया। मां बम्लेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ ही नहीं देश-विदेशों में भक्तों के लिए आस्था का केंद्र हैं। मां बम्लेश्वरी मंदिर का इतिहास 2500 वर्ष से भी प्राचीन बताया जाता है। केंद्र सरकार ने यहां प्रसाद योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर की परियोजना की घोषणा की है।

2. मां महामाया मंदिर रतनपुर

रतनपुर महामाया मंदिर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर में स्थित एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक सिद्ध शक्तिपीठ है। बिलासपुर-कोरबा मार्ग पर महामाया देवी का यह मंदिर 1050 ईसवी में बना बताया जाता है। राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा स्थापित



मंदिर क्षेत्र को कलचुरियों की राजधानी माना जाता है। यह कलचुरी राजाओं की कुलदेवी का ऐतिहासिक मंदिर है, जहाँ माता का कंधा गिरने की मान्यता है।

इस मंदिर का निर्माण 11वीं-12वीं शताब्दी (लगभग 12-13वीं शताब्दी) में कलचुरी वंश के राजा रतनदेव प्रथम द्वारा कराया गया था। बाद में 1492 ईस्वी (विक्रम संवत 1552) में राजा बहार साईं ने वर्तमान मंदिर का जीर्णोद्धार व निर्माण कराया। गर्भगृह में माँ महामाया की दुर्लभ दोहरी (ड्यूअल) प्रतिमा है - आगे महिषासुरमर्दिनी और पीछे देवी सरस्वती की आकृति विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ माता सती का दाहिना हाथ गिरा था।

3. मां दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में स्थित माँ दंतेश्वरी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि स्थानीय जनजातीय परंपरा और सनातन आस्था के अद्भुत मिलन का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह मंदिर दंतेवाड़ा में शंखिनी और डंकिनी नदियों के पवित्र संगम तट पर स्थित है, जो सदियों से आदिवासियों और आम लोगों की अगाध श्रद्धा का केंद्र रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यहाँ माता सती के दाँत गिरे थे, जिसके कारण इस पावन स्थल का नाम दंतेवाड़ा और माता का नाम दंतेश्वरी पड़ा। 14वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर की अधिष्ठात्री देवी को बस्तर के काकतीय राजा अपनी कुलदेवी मानते थे। मंदिर के गर्भगृह में काले पत्थर से निर्मित छह भुजाओं वाली महिषासुरमर्दिनी की भव्य मूर्ति स्थापित है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के दौरान इस मंदिर का महत्व सबसे चरम पर होता है। उत्सव के दौरान माता के छत्र और डोली को दंतेवाड़ा से जगदलपुर ले जाया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर-दूर से हजारों आदिवासी और आम श्रद्धालु पैदल पहुँचते हैं। यह आयोजन क्षेत्र की सांस्कृतिक एकता और आपसी भाईचारे को दर्शाता है।

4. मां बागेश्वरी कुदरगढ़ धाम

सूरजपुर जिले के ओडगी विकासखंड स्थित बागेश्वरी माता को राक्षसों के संहार के लिए जाना जाता है। यह शक्ति एवं साहस का प्रतीक माना जाता है। 1500 फीट ऊंचे पहाड़ों पर स्थित यह मंदिर चारों ओर घने जंगलों से घिरा है। मान्यता के अनुसार कुदरगढ़ क्षेत्र मां भगवती पार्वती की तपोस्थली रही हैं। जहां माता भगवती ने शक्ति का रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया था। बाद में इसी जगह पर लगभग चार सौ साल पहले राजा बालंद ने माता बागेश्वरी को स्थापित किया, वे माता के भक्त थे। बाद में चौहान वंश के राजा ने बालंद को युद्ध में पराजित कर दिया था, जिसके बाद उसी वंश ने माता के मंदिर की देख रेख की। तब से हर साल नवरात्र में सुबह की पहली आरती चौहान वंश के वंशज ही यहां करते हैं। 18वीं सदी में चौहान राजाओं ने छत्तीसगढ़ के मूल आदिवासी बैगा जनजाति को माता के देख-रेख और पूजा की जिम्मेदारी सौंपी थी, तब से आज तक बैगा समुदाय के लोग ही माता कि पूजा करते है।



5. मां चंद्रहासिनी चंद्रपुर

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले (पूर्व में जांजगीर-चांपा) के चंद्रपुर में महानदी के तट पर स्थित मां चंद्रहासिनी देवी का मंदिर एक प्रसिद्ध सिद्ध शक्तिपीठ है। यह मंदिर महानदी और मांड नदी के संगम के पास चंद्रपुर में स्थित है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार, संबलपुर के राजा चंद्रहास ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसके कारण इस स्थान का नाम %चंद्रपुर% और देवी का नाम %चंद्रहासिनी% पड़ा। वर्ष 1522 में चांद्रपुर के गोंड राजा धुंध्या राम साह अत्राम ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। गोंड राजाओं ने मां को अपनी कुलदेवी माना और शक्ति पूजा की परंपरा को आगे बढ़ाया।

सक्ती जिला स्थित मां चंद्रहासिनी मंदिर का इतिहास काफी प्राचीन है। यह चंद्रपुर की पहाड़ी पर स्थित हैं। मंदिर की सुंदर कलाकृति प्राचीनता का अनुभव कराती है। लोगों की माता को लेकर बड़ी आस्था है। इसे 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, और ऐसी मान्यता है कि यहां माता सती का बायां कान गिरा था। वर्ष 1935 में महानदी में भीषण बाढ़ आई थी। तब राजा चंद्रहास के वंशज ठाकुर शशिभूषण ने माता को बकरा बलि अर्पित कर प्रार्थना की, जिसके बाद नदी का जलस्तर कम हो गया और लोगों की जान बची। आज भी नदी के पास पत्थर पर माता के पद-चिह्न मौजूद हैं, जिनकी पूजा की जाती है।

राज्य के आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पारिस्थितिकी दृष्टि से संवहनीय पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन, अनुभव की गुणवत्ता एवं आकर्षण को सुदृढ़ करना, छत्तीसगढ़ की समृद्ध एवं विविध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रचार-प्रसार करना, आर्थिक विकास एवं संबन्धित क्षेत्रों में पर्यटन के योगदान में वृद्धि करना। पर्यटन से संबन्धित अधोसंरचना के विकास में निजी निवेशकों के प्रयत्नों को प्रोत्साहित करना। शासन की भूमिका को सुविधापरक बनाना, पर्यटन के क्षेत्र में नई अवधारणाएं जैसे- टाइम शेयर, पारिस्थितिकी पर्यटन, साहसिक पर्यटन, इत्यादि को बढ़ावा देना। स्थानीय समुदाय की बौद्धिक सम्पदा एवं अधिकारों का सम्मान करना। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देना, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलने की संम्भावना होगी।

जिंदगी से जुड़ी फील्ड है एनवायरनमेंटल साइंस

एनवायरनमेंटल साइंस ऊर्जा को बचाने, बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ग्राउंड वॉटर आदि के अध्ययन वाला विषय है। एकेडमिक तौर पर देखें तो एनवायरनमेंटल साइंस का दायरा काफी व्यापक है और इस कोर्स में अध्ययन के दौरान सिर्फ भौतिकी या बायोलॉजिकल साइंस का ही नहीं बल्कि इकोलॉ जी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी और ज्योलॉजी का भी अध्ययन किया जाता है।



पर्यावरण हमारी जिंदगी में अहम भूमिका निभाता है। चाहे बात खाने के अनाज की हो, रहने के लिए घर की हो, पहनने के लिए कपड़े की हो या फिर पानी, सूर्य की रोशनी, हवा की हो। सभी कुछ इसी पर्यावरण पर निर्भर करता है। इसलिए जब पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है तो उसका कहीं न कहीं प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। औद्योगिक विकास की रफ्तार ने पर्यावरण को लीलने का काम किया है। यही कारण है कि सभी का ध्यान इस ओर गया है। ऐसे में, एनवायरनमेंटल साइंस से जुड़े लोगों की मांग काफी बढ़ गई है। मूल रूप से एनवायरनमेंटल साइंस ऊर्जा को बचाने, बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ग्राउंड वॉटर आदि के अध्ययन वाला विषय है। एकेडमिक तौर पर देखें तो एनवायरनमेंटल साइंस का दायरा काफी व्यापक है और इस कोर्स में अध्ययन के दौरान सिर्फ भौतिकी या बायोलॉजिकल साइंस का ही नहीं बल्कि इकोलॉ जी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी और ज्योलॉजी का भी अध्ययन किया जाता है।

एनवायरनमेंटल साइंस के अध्ययन की बात पहली बार 1977 में स्टॉकहोम में हुई कांफ्रेंस में सामने आई थी। औद्योगिक विकास की अंधी दौड़ में आज जिस तरह पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, वह किसी से अछूता नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से लेकर ग्लेशियर के पिघलने या फिर पर्यावरण प्रदूषण आदि का मामला सभी कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। आज के दौर में सरकार से लेकर स्वयंसेवी संगठन तक सभी पर्यावरण को लेकर जागरूक हो रहे हैं। एनवायरनमेंटल साइंस से संबंधित कोर्स यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले छात्र कंस्ट्रक्शन, केमिकल, मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी के फील्ड में करियर बना सकते हैं। इसके अलावा और भी कई फील्ड हैं जहां इससे संबंधित डिग्री हासिल करने वाले छात्र करियर को नई मंजिल तक पहुंचा सकते हैं।

एनवायरनमेंटल साइंटिस्ट

इससे जुड़े लोग वातावरण पर मनुष्यों द्वारा पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करते हैं। वे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लेकर शोध करते हैं और एनवायरनमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिस को लेकर संबद्ध संस्थानों को सुझाव भी देते हैं।



एनवायरनमेंटल इंजीनियर्स

इस फील्ड से जुड़े लोग वास्ट मैनेजमेंट, लीन मैन्युफैक्चर, रिसाइक्लिंग, इमिशन कंट्रोल, इनवायरेनमेंटल सस्टेनेबिलिटी और पब्लिक हेल्थ मामलों का अध्ययन करते हैं।

एनवायरनमेंटल लॉबिस्ट

ये सरकारी अधिकारियों, नेताओं और संबंधित स्वयंसेवी संस्थानों को पर्यावरण मामलों और नीतियों की जानकारी देते हैं।

एनवायरनमेंटल एजुकेटर

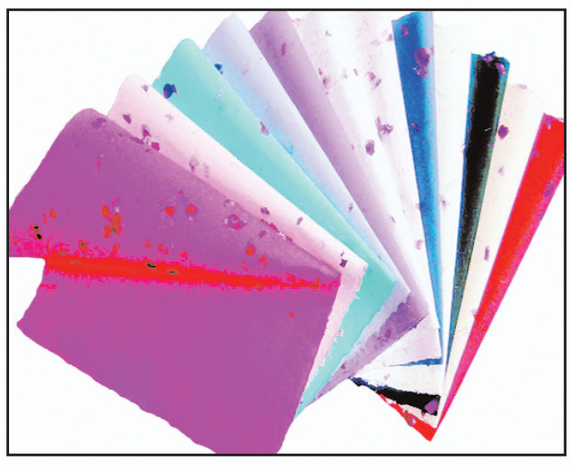
इससे जुड़े लोग एनवायरनमेंटल साइंस या फिर इससे संबंधित विषयों यानी इकोलॉजी या हाइड्रोलॉजी छात्रों को पढ़ाते हैं। इसके अलावा, एनवायरनमेंटल बायोलॉजिस्ट, एनवायरनमेंटल मॉडलर्स, एनवायरनमेंटल जर्नलिस्ट या पर्यावरण से संबंधित तकनीकविदों की तरह भी कार्य कर सकते हैं।

वेतन – एनवायरनमेंटल साइंस में बैचलर डिग्री करने वाले छात्रों को आसानी से 15-30 हजार रुपये मासिक की नौकरी मिल जाती है। जिन्होंने इस विषय में पोस्ट ग्रेजुएट किया है, उन्हें कम से कम 35-50 हजार रुपये मासिक तौर पर तो मिलते ही हैं। जो लोग पीएचडी करने के बाद बतौर साइंटिस्ट या कंसल्टेंट कार्य करते हैं, उनका वेतन शुरुआत में 50-75 हजार रुपये के बीच होता है।

संस्थान – अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, यूपी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंटल बायोलॉजी, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली स्कू ल ऑफ एनवायरनमेंटल साइंसे ज, जेएनयू, नई दिल्ली पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, यूपी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, यूपी

हस्तनिर्मित कागज उद्योग फलता-फूलता रोजगार

भारत में हस्तनिर्मित कागज उद्योग का इतिहास बहुत पुराना है। मुगल काल से इसके प्रमाण मिलते हैं। यह उद्योग भारत के सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें सबसे खास बात यह है कि यह उद्योग अपशिष्ट पदार्थ को रिसाइकिलिंग प्रणाली द्वारा उच्चकोटि के कागज में तब्दील कर देता है। इसके अलावा, इसमें कम खर्च में अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है। असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं नगालैंड जैसे राज्यों में हस्तनिर्मित कागज के उद्योग खूब फल फूल रहा है। जबकि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 10-15 हजार लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं।



शैक्षिक योग्यता की दरकार

इस रोजगार को प्रारंभ करने से पहले यदि आप प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना बहुत जरूरी है। प्रशिक्षण के पश्चात आप विशेष योग्यता से लैस हो जाएंगे, बल्कि रोजगार से संबंधित बारीकियां भी आपको मालूम हो सकेंगी। यदि आपके पास इस व्यवसाय से संबंधित जानकारी पहले से ही मौजूद है तो पांचवीं की डिग्री भी महत्वपूर्ण है यानी आपको सिर्फ साक्षर होना आवश्यक है। उम्र-सीमा 18 वर्ष से कम न हो।

संबंधित पाठ्यक्रम

इसमें मुख्यत- हैंडमेड पेपर में सर्टिफिकेट कोर्स (एक से दो सप्ताह), पेपर कंजरवेशन कोर्स (दो माह), इंटरप्रिन्योरशिप कोर्स (दो माह) तथा हैंडमेड पेपर में एडवांस कोर्स (एक वर्ष) आदि शामिल हैं।

फीस एवं प्रशिक्षण अवधि

यदि आप प्रशिक्षण खादी ग्राम उद्योग कमीशन (केवीआईसी) से प्राप्त करते हैं तो आपको सिर्फ 200 रुपए मामूली फीस में प्रशिक्षण मिल सकता है। जबकि प्रशिक्षण अवधि 2-3 हफ्तों की होती है। इस दौरान प्रशिक्षु को अपशिष्ट पदार्थों को रिसाइकिल कर आकर्षक कागज में परिवर्तित करने की कला सिखा दी जाती है। रिसाइकिलिंग में टेलर कटिंग, होजरी कटिंग तथा छोटे-छोटे टुकड़ों के सहारे उच्चकोटि के उपयोगी पेपर तैयार किए जाते हैं।

खर्च एवं सुविधा

हस्त निर्मित कागज उद्योग का यूनिट लगाने में कम से कम 40-70 हजार रुपए की लागत आती है। प्रारंभ में यह जरूरी है कि यूनिट छोटी ही लगाई जाए। बाद में सफल होने तथा डिमांड अधिक होने पर यूनिट की क्षमता इच्छानुसार बढ़ा सकते हैं। इस रोजगार के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किसी भी व्यक्ति को प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए तक के ऋण का प्रबंध किया है। इसके साथ ही महिलाओं, अनुसूचित जातियों,

प्रशिक्षण दिलाने वाले संस्थान

ऐसे कई संस्थान हैं जो अपने यहां से हस्तनिर्मित कागज से जुड़ा प्रशिक्षण दिलाते हैं-

- खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (गांधी दर्शन), राजघाट, नई दिल्ली-110002 (संस्थान का पूरे भारत में कई जगह प्रशिक्षण केंद्र मौजूद)
- डॉ राजेन्द्र प्रसाद मल्टी डिस्प्लीनरी ट्रेनिंग सेंटर, खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, शेखपुरा, पटना-14
- कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीटच्यूट, सांगानेर, राजस्थान-302022

टूरिज्म गाइड, मेहनती युवाओं के लिए

पर्यटन आज सांस्कृतिक पहचान पुख्ता करने के साथ रेवेन्यू अर्जित करने का भी जरिया बन रहा है। ऐसे में स्थानीय सरकारें देश में पर्यटन को बढ़ावा देने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। भारतीय गांवों की सैर विदेशी पर्यटकों के लिए किसी रोमांच से कम नहीं है। यहां के घर, बच्चों के खेल, महिलाओं का ओढना-पहनना, खेत-खलिहान, दैनिक गतिविधियां, अर्थव्यवस्था आदि उन्हें इतने आकर्षित करते हैं कि पर्यटक महीनों यहां डेरा डाले रहते हैं।

टूरिस्ट गाइड का कार्य

किसी भी देश की सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराओं से पर्यटकों को अवगत कराने में टूरिस्ट गाइड की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। टूरिस्ट गाइड पर्यटकों के साथ रहकर उन्हें जाने-अनजाने और अनछुए पहलुओं से वाकिफ कराते हैं। यही वो कारण है जिसके चलते आज टूरिस्ट गाइड एक आकर्षक कॅरियर विकल्प के तौर पर अपनी जगह बना चुका है। संबंधित देश के टूरिस्ट गाइड राज्य क्षेत्र की भौगोलिक जानकारी के साथ-साथ सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पर्यटन संबंधी जानकारी रखने के साथ ट्रेवल एजेंसी और बड़े-बड़े होटलों की जानकारी रखते हैं। देश में टूरिस्ट गाइड के लिए भारतीय पर्यटन और ट्रेवल विभाग से टूरिस्ट गाइड का लाइसेंस लेना होता है। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है।

कोर्स और क्वालिफिकेशन – देश के अलग-अलग संस्थान टूरिज्म ट्रैवल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्स संचालित करते हैं, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म (आईआईटीएम) सबसे खास है, तो वहीं संबंधित राज्य व केंद्र सरकारों के पर्यटन विभाग भी टूरिस्ट गाइड ट्रेनिंग कोर्स आयोजित करते हैं। जिन्हें पास करने पर आपको सर्टीफाइड गाइड का लाइसेंस मिलता है। टूरिज्म के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए जरूरी है कि वे इस क्षेत्र में औपचारिक शिक्षा भी ग्रहण करें। देश में विभिन्न संस्थान एवं विश्वविद्यालय टूरिज्म में डिप्लोमा, बैचलर डिग्री एवं मास्टर्स डिग्री प्रदान करते हैं। डिप्लोमा कोर्स की अवधि अमूमन एक वर्ष होती है, जिसे ग्रेजुएशन के बाद किया जा सकता है। आईसीसीआर इस क्षेत्र में जूनियर फेलोशिप भी प्रदान करता है।

कॅरियर ऑप्शन – स्थानीय पर्यटन उद्योग, राष्ट्रीय पर्यटन उद्योग, होटल इंडस्ट्री, टैवल एजेंसी, एविएशन, कार्गो ऑपरेशन, हॉस्पिटेलिटी आदि में टूरिस्ट गाइड के लिए अवसर बाट जोह रहे हैं। टूरिज्म उद्योग के विस्तार से टूरिस्ट गाइड का स्कोप बढ़ा है। मेहनती, कुशल और ईमानदार युवा चाहें तो भारत की संपन्न विरासत से अपने लिए समृद्ध भविष्य की राह खोज सकते हैं। भारत सरकार भी अब ग्रामीण पर्यटन को बढावा देने के लिए कदम उठा रही है। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष देश भर में 66 लाख विदेशी सैलानी आए, जिनसे करीब 17 ।75 अरब डॉलर की कमाई हुई। मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष इनकी संख्या में 12 फीसदी बढोत्तरी का लक्ष्य रखा है ताकि वर्ष 2016 तक पर्यटन से विदेशी मुद्रा की

क्यों जरूरी है अपनी स्किल्स में इजाफा करना?

आप करियर के उस मुकाम पर खड़े हैं, जहां सोचते हैं कि अगले दस सालों में आप क्या करने जा रहे हैं? क्या कभी इस बात का भी अफसोस होता है कि आपने पढ़ाई के दौरान अलग-अलग विषयों का चुनाव क्यों नहीं किया, ताकि कुछ और पढ़ने या किसी दूसरी दिशा में करियर बनाने के बारे में सोच पाते? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हां है तो यह समय है अपने पास मौजूद विकल्पों पर गंभीरता से विचार करने का। खुद की स्किल्स में निवेश करके अपने आप को आगे बढ़ाने का, री-स्किलिंग का।



क्या है स्किल्स में इजाफा करना?

शब्दकोष में री-स्किलिंग का अर्थ होगा, वह प्रशिक्षण और अनुभव, जिसके जरिए नई और बेहतर स्किल्स की जानकारी मिलती है। करियर में किसी उम्मीदवार में नई स्किल्स हासिल करने, सीखने और खुद को बदलने की क्षमता और इच्छा का होना बेहद अहम गुण माना जाता है। यह दूरदर्शिता होना कि करियर को आगे ले जाने के लिए किन स्किल्स की जरूरत होगी और उस दिशा में कदम बढ़ाना किसी उम्मीदवार के करियर को आगे ले जाने में मदद करता है। आईआईएम-बेंगलुरु में चाइनीज बिजनेस लैंग्वेज कोर्स पढ़ाने वाले प्रो. एस स्वामीनाथन कहते हैं, 'अपनी स्किल्स में इजाफा करने का अर्थ सक्रिय होकर केवल नई स्किल सीखना भर नहीं है। यह नौकरी से ब्रेक लेकर उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ाना भी हो सकता है। उदाहरण के लिए कई आईआईएम केंद्रों में मंडारिन एक लोकप्रिय लैंग्वेज कोर्स बन कर उभरा है। वर्तमान में भारत-चीन एक-दूसरे से व्यापारिक रिश्तों को नकार नहीं सकते। विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने के लिए इस दिशा में कदम बढ़ाना जरूरी भी होगा। ऐसे में चाइनीज बिजनेस कोर्स की मदद से विद्यार्थी दोनों देशों में बन रहे आर्थिक समीकरणों में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं।' कॉलेज के दौरान लिए गए विषय निश्चित तौर पर पसंदीदा जॉब हासिल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पर ऐसे भी मामले मिलते हैं, जहां लोग संयोगवश दूसरे क्षेत्रों में करियर बना बैठते हैं या फिर अपने करियर के दौरान ऐसे फंस जाते हैं, जहां उनके लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि अब वे किस ओर कदम बढ़ाएं। दो से तीन वर्ष नौकरी कर चुकने वाले विशेषज्ञता प्राप्त उम्मीदवार और बड़े अधिकारी भी यह मानते हैं कि बदलावों से गुरेज करना और अपनी स्किल्स को बढ़ाने का प्रयास न करना एक स्तर पर आकर उम्मीदवार की प्रगति को बाधित कर देता है। जिस तेजी से कार्यस्थल और उनकी नीतियां बदल रही हैं, यह पहले से भी जरूरी हो गया है कि उम्मीदवार खुद को उपयोगी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। थोलोंस ग्लोबल इंस्टीट्यूट में एमडी अंकिता वशिष्ठ के अनुसार, 'जॉब मार्केट में खुद को रोजगार योग्य और उपयोगी बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। वर्कप्लेस पर बढ़ती विविधता और नित बदलती तकनीक ने कर्मचारियों पर नई तकनीक और कार्य प्रणाली को सीखने का दबाव बनाया है। उदाहरण के लिए, यदि कोई नई तकनीक मसलन बिग डाटा और एनालिटिक्स में करियर बनाना चाहता है तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स में क्रैश कोर्स करना फायदेमंद हो सकता है। एक परंपरागत मार्केटिंग व्यक्ति के लिए डिजिटल मार्केटिंग में अनुभव बढ़ाना लाभप्रद रहेगा। इसी तरह अन्य उम्मीदवार खुद को किसी ऑनलाइन कोर्स या डेवलमेंट प्रोग्राम से भी जोड़ सकते हैं।' ग्लोबल रिक्रूटमेंट फर्म केली सर्विसेज के हालिया अध्ययन के अनुसार विश्व परिदृश्य की तुलना में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बड़े स्तर पर कर्मचारी तेजी से उभरते बाजार में अपनी स्किल्स में इजाफा करने की इच्छा जता रहे हैं। 69% भारतीय कर्मचारी आगे बढ़ने के लिए उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण हासिल करने के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं। यह संख्या यूरोप और अमेरिका की तुलना में अधिक है। पहले बैंकों में नौकरी में उन्हीं लोगों को रखा जाता था, जो पहले बैंक में नौकरी करते रहे हैं। इसी तरह एफएमसीजी कंपनियां भी इसी क्षेत्र के अनुभव को वरीयता देती थीं। पर वह समय बीत गया है। आज कंपनियां विविध क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वालों को रखना पसंद करती हैं। यानी गतिशील बाजार में खुद को रोजगार योग्य बनाने व उच्च पदों को कुशलता से संभालने के लिए प्रशिक्षण हासिल करने की जरूरत होगी ही।'

रोचक तथ्य – 57 प्रतिशत प्रतिभागियों ने अपने वर्तमान नियोक्ता के पास ही पदोन्नति को ध्यान में रखते हुए अपनी स्किल्स में इजाफा करने की इच्छा जतायी। वहीं 47 प्रतिशत के अनुसार वे दूसरी कंपनी में जाने के लिए अपनी स्किल्स में इजाफा करना पसंद करेंगे।

70 प्रतिशत के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी स्किल नौकरी करते हुए हासिल की जा सकती है। उसके बाद 58 प्रतिशत ने शिक्षा और प्रशिक्षण को जरूरी बताया है। 26 प्रतिशत के अनुसार सेमिनार और वेबिनार से भी नई स्किल सीखने में मदद मिलती है। 42 प्रतिशत के

न्यूज इन शॉर्ट

भीषण सड़क हादसे में विधायक के भाई की दर्दनाक मौत

मुंगेली। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में गुरुवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों में मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले के भाई अधीन मोहले भी शामिल हैं। हादसा विधायक के गृह ग्राम दशरंगपुर में सुबह करीब 6 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे खड़े लोगों को तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में अधीन मोहले समेत तीन लोगों की जान चली गई। दुर्घटना के बाद पिकअप चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं, तीन लोगों की एक साथ मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।जानकारी के मुताबिक, गुरुवार सुबह करीब 6 बजे विधायक पुन्नूलाल मोहले के भाई अधीन मोहले मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे। इस दौरान वे अपने घर के बाहर सड़क किनारे कुछ लोगों के साथ खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार पिकअप वाहन वहां पहुंचा और अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी। हादसा इतना गंभीर था कि तीन लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों के बीच शोक का माहौल बन गया।प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के मुताबिक, दुर्घटना के बाद पिकअप वाहन का चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल वाहन के पंजीयन नंबर, मालिक और चालक की पहचान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस हादसे में शामिल वाहन का पता लगाने के लिए जांच कर रही है। घटनास्थल और आसपास के मार्गों से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि फरार वाहन और उसके चालक की पहचान की जा सके।
बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में एक पिकअप वाहन नजर आया है, जो तखतपुर की ओर से मुंगेली की तरफ जा रहा था।

पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से फरार हुआ आरोपी, मचा हड़कंप

महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पुलिस अभिरक्षा से आरोपी के फरार होने का मामला सामने आया है। नशीली टैबलेट की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार 20 वर्षीय युवक महासमुंद मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल से पुलिस जवानों को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी को तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसकी सुरक्षा और निगरानी के लिए दो पुलिस जवान तैनात किए गए थे। इसके बावजूद गुरुवार सुबह आरोपी अस्पताल से भाग निकला। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है, वहीं सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक की भी जांच की जा रही है।
जानकारी के मुताबिक, सरायपाली पुलिस ने बुधवार को ओडिशा से नशीली टैबलेट की तस्करी करने के आरोप में दिनेश सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पेट के दाहिने हिस्से में तेज दर्द होने और झटके आने की शिकायत की थी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को देखते हुए पुलिस ने उसे पहले सरायपाली में प्राथमिक उपचार दिलाया। इसके बाद चिकित्सकों की सलाह पर आरोपी को बेहतर इलाज के लिए महासमुंद मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल रेफर किया गया था।अस्पताल में इलाज के दौरान आरोपी की निगरानी के लिए दो पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी। इनमें खोमनलाल साहू और रामचरण यादव शामिल थे। दोनों जवानों को आरोपी की सुरक्षा और अभिरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन गुरुवार सुबह आरोपी मौका पाकर अस्पताल से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 7:30 बजे से 8:30 बजे के बीच एक पुलिस जवान बाथरूम गया हुआ था, जबकि दूसरा डॉक्टर से संबंधित कार्य में व्यस्त था। इसी दौरान आरोपी दिनेश सिंह राजपूत अस्पताल से निकलने में कामयाब हो गया।पैर में रॉड लगी होने के बावजूद भाग निकला इस घटना का एक हैरान करने वाला पहलू यह भी है कि आरोपी के पैर में पहले से रॉड लगी हुई थी।

सेवा सेतु से आसान हुई सरकारी सेवाओं की राह, अजय कुमार के पुत्र को कुछ ही दिनों में मिला स्थायी जाति प्रमाण पत्र

एक सदस्य का जाति प्रमाण पत्र बनने से परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी प्रक्रिया हुई आसान

मोबाइल पर व्हाट्सऐप से मिली प्रमाण पत्र की डिजिटल प्रति, हार्ड कॉपी भी हुई उपलब्ध

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवाओं को सरल, सुगम और समयबद्ध बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का लाभ आम नागरिकों को मिल रहा है। सेवा सेतु केन्द्रों के माध्यम से अब आवश्यक प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक हो रही है। जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा तहसील अंतर्गत ग्राम सांकर निवासी श्री अजय कुमार का अनुभव इसका उदाहरण है। उन्होंने अपने पुत्र के आय, निवास एवं जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सेवा सेतु केन्द्र अकलतरा में आवेदन किया था। आवेदन के कुछ ही दिनों के भीतर उनके पुत्र का स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो गया। प्रमाण पत्र की डिजिटल प्रति व्हाट्सऐप के माध्यम से उनके मोबाइल पर उपलब्ध कराई गई और हार्ड कॉपी भी शीघ्र प्रदान कर दी गई।



'कुछ ही दिनों में मिला प्रमाण पत्र, अनावश्यक इंतजार से मिली राहत'

श्री अजय कुमार अपने पुत्र के आवश्यक दस्तावेज बनवाने के लिए तहसील कार्यालय अकलतरा स्थित सेवा सेतु केन्द्र पहुंचे थे। उन्होंने आय, निवास और जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ ही दिनों में उनके पुत्र का स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया।

महतारी वंदन योजना बनी अनीता की आर्थिक मजबूती का सहारा, घरेलू खर्चों के साथ भविष्य के लिए भी कर रहीं बचत

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

रायपुर। घर की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के साथ भविष्य के लिए कुछ बचत कर पाना हर महिला की इच्छा होती है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित महतारी वंदन योजना प्रदेश की महिलाओं की इसी आकांक्षा को पूरा करने में मददगार बन रही है। योजना के तहत प्रतिमाह मिलने वाली एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता महिलाओं को अपनी जरूरतों के लिए आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम अमोरा निवासी श्रीमती अनीता कश्यप भी इस योजना से लाभान्वित होकर घरेलू खर्चों का बेहतर प्रबंधन करने के साथ भविष्य के लिए छोटी-छोटी बचत कर रही हैं।



घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ बचत की भी बनी आदत

श्रीमती अनीता कश्यप को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हर महीने एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। वे इस राशि का उपयोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं और परिवार के छोटे-मोटे घरेलू खर्चों को पूरा करने में करती हैं। इसके साथ ही खर्चों के बाद बची राशि को भविष्य की जरूरतों के लिए सुरक्षित रखने का प्रयास भी करती हैं। नियमित आर्थिक सहायता मिलने से उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खर्चों की योजना बनाने में सुविधा हो रही है।
अनीता के लिए महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि केवल घरेलू खर्चों में सहयोग का माध्यम नहीं, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ने का अवसर भी है। छोटी-छोटी बचत के माध्यम से वे भविष्य में आने वाली आवश्यकताओं के लिए आर्थिक तैयारी कर पा रही हैं। इससे उन्हें अपनी जरूरतों के संबंध में निर्णय लेने और परिवार के खर्चों में योगदान देने का आत्मविश्वास मिल रहा है।

हर महीने की सहायता से बढ़ रहा आर्थिक आत्मविश्वास

श्रीमती अनीता कश्यप बताती हैं कि महतारी वंदन योजना से मिलने वाली नियमित राशि उनके लिए उपयोगी साबित हो रही है। इससे वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ कुछ पैसे बचाने का भी प्रयास करती हैं। हर महीने सहायता राशि प्राप्त होने से घरेलू खर्चों का प्रबंधन करना आसान हुआ है और भविष्य की जरूरतों के लिए बचत करने की प्रेरणा भी मिली है।
उन्होंने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाली इस जनकल्याणकारी योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। श्रीमती अनीता कश्यप की यह कहानी दर्शाती है कि प्रतिमाह मिलने वाली एक हजार रुपये की सहायता राशि भी महिलाओं के दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

पुल-पुलियों के विकास को गति मिलेगी

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की पहल से भटगांव विधानसभा में 6.97 करोड़ रुपये के सड़क-पुल कार्यों को मिली स्वीकृति

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री और भटगांव विधायक श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से भटगांव विधानसभा क्षेत्र में आवागमन सुविधाओं के विस्तार के लिए दो महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। इन कार्यों पर कुल 6 करोड़ 97 लाख 80 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।स्वीकृत कार्यों में गंगोटी-शिवप्रसादनगर से डुमरिया मार्ग पर गोबरी नदी में उच्चस्तरीय पुल और पहुंच मार्ग का निर्माण शामिल है। इस कार्य के लिए 3 करोड़ 51 लाख 29 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। पुल बनने से नदी के दोनों ओर बसे गांवों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और क्षेत्रीय संपर्क बेहतर होगा।इसी तरह ग्राम पंचायत कुम्दाबस्ती से जुना तालाब बांधभीठ तक 2.40 किलोमीटर मार्ग का निर्माण पुल-पुलियों सहित किया जाएगा। इस कार्य के लिए 3 करोड़ 46 लाख 51 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। मार्ग बनने से स्थानीय निवासियों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी और क्षेत्र के संपर्क मार्गों का विस्तार होगा।मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास और ग्रामीण अंचलों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इन कार्यों की स्वीकृति से भटगांव विधानसभा क्षेत्र में सड़क और पुल-पुलियों के विकास को गति मिलेगी।



वित्तीय वर्ष 2026-27 में सर्वेयरों के मानदेय के लिए 2,333.33 लाख रुपये का आवंटन जारी

डिजिटल क्रॉप सर्वे के भुगतान संबंधी शिकायत पर कृषि विभाग ने की कार्यवाही

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों से संबंधित कृषि गतिविधियों के संचालन एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे के कार्यों के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। डिजिटल क्रॉप सर्वे में संलग्न सर्वेयरों के मानदेय भुगतान के संबंध में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर प्राप्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग को प्रकरण का परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एग्रीस्टैक परियोजना के अंतर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य में संलग्न सर्वेयरों के मानदेय भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में दो किस्तों में राशि आवंटित की गई है। इनमें प्रथम किस्त के रूप में 1,399.99 लाख रुपये तथा द्वितीय किस्त के रूप में 933.33 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार कुल 2,333.33 लाख रुपये का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। विभागीय पत्र में उल्लेखित विवरण के अनुसार, उक्त आवंटन में से 1,109.16 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रतिवेदित है, जो कुल आवंटन का 47.54 प्रतिशत है। शेष राशि के व्यय एवं भुगतान की स्थिति का नियमानुसार परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायत पर विभागीय कार्रवाई

जिला बालोद के डौंडीलोहारा विकासखंड अंतर्गत ग्राम रेंगाडबरी निवासी सत्यानंद नायक द्वारा डिजिटल क्रॉप सर्वे के कार्य के मानदेय का भुगतान नहीं होने के संबंध में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आवेदक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में किए गए डिजिटल क्रॉप सर्वे के कार्य का भुगतान अब तक प्राप्त नहीं होने की बात कही थी।प्राप्त शिकायत का कृषि विभाग ने उपलब्ध अभिलेखों एवं आवंटित राशि के विवरण के आधार पर प्रकरण का परीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।शासकीय अभिलेखों के अनुसार, शिकायत का निराकरण संबंधित विभागीय प्रक्रिया के अंतर्गत अपेक्षित है। विभाग को निर्देशित किया गया है कि शिकायत में उल्लेखित तथ्यों की जांच करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा प्रकरण के निराकरण की स्थिति सुनिश्चित की जाए।

पारदर्शिता के साथ शिकायतों के निराकरण पर जोर

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को संबंधित विभागों तक पहुंचाकर उनके परीक्षण एवं निराकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के मानदेय भुगतान से संबंधित इस प्रकरण में भी संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। इससे शिकायतों के परीक्षण, विभागीय जवाबदेही तथा लंबित प्रकरणों के नियमानुसार निराकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता से खेती-किसानी के खर्चों का प्रबंधन

पीएम-किसान सम्मान निधि बनी उमेन्द्र की खेती का सहारा, खाद-बीज की जरूरतों को पूरा करने में मिल रही मदद

सीधे बैंक खाते में मिल रही सम्मान निधि, किसान उमेन्द्र यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति जताया आभार

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

खेती-किसानी में समय पर खाद, बीज और अन्य जरूरी संसाधनों की उपलब्धता किसानों के लिए महत्वपूर्ण होती है। विशेषकर फसल की तैयारी के समय छोटी-छोटी कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक संसाधनों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम सलखन निवासी किसान श्री उमेन्द्र यादव भी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। उन्हें प्रतिवर्ष तीन समान किस्तों में मिलने वाली 6 हजार रुपये की सहायता राशि खेती-किसानी के जरूरी खर्चों को पूरा करने में मददगार साबित हो रही है।



'खाद-बीज की व्यवस्था में मिल रही राहत, खेती की तैयारी हुई आसान'

श्री उमेन्द्र यादव के लिए खेती-किसानी आजीविका का प्रमुख आधार है। फसल की बुआई और कृषि कार्यों की तैयारी के दौरान खाद, बीज एवं अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करना जरूरी होता है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए समय पर राशि उपलब्ध होना किसानों के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता उमेन्द्र यादव को इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग प्रदान कर रही है।
श्री उमेन्द्र यादव बताते हैं कि खेती के दौरान कई ऐसे छोटे-छोटे खर्च होते हैं, जिनके लिए समय पर पैसों की जरूरत पड़ती है। सम्मान निधि की राशि से खाद-बीज की खरीदी और अन्य कृषि कार्यों की तैयारी में मदद मिलती है। इससे खेती से जुड़े आवश्यक खर्चों का प्रबंधन करना उनके लिए अधिक सुविधाजनक हुआ है।

'तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में मिलते हैं 6 हजार रुपये'

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि दो-दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। इस व्यवस्था से किसानों को कृषि संबंधी आवश्यकताओं और अन्य जरूरतों के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध होता है।
श्री उमेन्द्र यादव को भी योजना के तहत नियमित आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। उनके लिए यह राशि खेती की तैयारी के समय आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करने और कृषि कार्यों को सुचारू रूप से जारी रखने में उपयोगी साबित हो रही है।

'सम्मान निधि से मिला आर्थिक संबल, किसान ने जताया आभार'

श्री उमेन्द्र यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से मिलने वाली सहायता राशि खेती-किसानी के जरूरी खर्चों को पूरा करने में सहयोग करती है। उन्होंने इस आर्थिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।
सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत श्री उमेन्द्र यादव की यह कहानी दर्शाती है कि किसानों को मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता खेती-किसानी की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को समय-समय पर आर्थिक सहयोग मिल रहा है, जिससे उन्हें कृषि कार्यों की तैयारी और जरूरी संसाधनों की व्यवस्था करने में सुविधा हो रही है।

एक सत प्रयास जनकल्याण समिति के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **अभिषेक शर्मा** द्वारा 202, भाटागांव चौराहा , रायपुर (छत्तीसगढ़) पिन 492015 से प्रकाशित एवं आसमा पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड , गॉस मेमोरियल हाल के पास , जयस्तंभ चौक, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित।
संपादक - रिज़वान आज़म, **समूह संपादक**- महेश कुमार तिवारी ईमेल - eksatbulletin@gmail.com R.N.I Number - CHHHIN/2020/78457 पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार ।